भारतीयों के साथ धोखा

भारतीयों का किसी विदेशी जंग में मारा जाना जितना दुखद है, उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। दुखद इसलिए कि भारतीयों को युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया गया और शर्मनाक इसलिए कि हम भारत से अपने युवाओं के पलायन या विदेश यात्रा की निगरानी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने देर से ही सही, कदम उठाया है और आकर्षक नौकरियों के बहाने भारतीय युवाओं को रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भेजने की साजिश में शामिल एक प्रमुख मानव तस्कर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में अनेक ठिकानों पर तलाशी ली है। दरअसल, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना आज समय की बड़ी मांग है। अनेक वीजा सलाहकार कंपनियों और एजेंटों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, तो इन सभी के बारे में लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि वे सतर्कता बरतें। काश! इन धोखेबाज कंपनियों पर पहले ही शिकंजा कसा जाता, तो आज अनेक युवा असुरक्षा का शिकार होने से बच जाते।

सीबीआई की सक्रियता तब सामने आई है, जब विदेशी जंग के मोर्चे पर भारतीयों के मारे जाने की खबर आने लगी है। हैदराबाद के 30 वर्षीय मोहम्मद अफसान के यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में मारे जाने के बाद खासतौर पर जागरूकता बढ़ी है। अफसान को धोखे से रूसी सेना में शामिल किया गया था। एक सप्ताह पहले सूरत के हामिल मंगुकिया की भी मौत विदेशी मोर्चे पर हुई है। सबसे दुखद बात है कि रूस ने मौत की पुष्टि की है, लेकिन युवक को विदेश भेजने वाला एजेंट अभी भी लोगों को बरगलाने में जुटा है। ऐसे एजेंटों पर प्रशासन अगर पूरी सख्ती से शिकंजा कसे, तो ही लोगों के बीच सही संदेश जाएगा। अफसान और हामिल जैसे युवा सैकड़ों में हो सकते हैं। विगत समय में कई नौजवानों को रूस में मोटी तनख्वाह के साथ रोजगार का झूठा आश्वासन दिया गया है और बताया गया है कि उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। एजेंटों ने इन युवाओं से लाखों रुपये लेकर रूस भेजा है। कथित रूप से वहां इन युवाओं को दो विकल्प दिए गए हैं या तो दस साल की जेल स्वीकार करें या फिर सेना में शामिल हो जाएं। जाहिर है, ज्यादातर युवाओं ने कैद के बजाय सैन्य सेवा को चुना है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले सात युवाओं के एक समूह ने भारतीय अधिकारियों से सहायता के लिए गुहार लगाई है। इन नौजवानों का भी आरोप है कि उन्हें रूसी सैन्य सेवा में शामिल करके धोखा दिया गया है।

आकर्षक नौकरियों के बहाने भारतीय युवाओं को रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भेजने की साजिश में शामिल एक प्रमुख मानव तस्कर नेटवर्क का भंडाफोड़ सुखद है।

जहां तक भारत सरकार या विदेश मंत्रालय का संबंध है। पिछले महीने ही रूसी सेना में सहायक भूमिकाओं के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती की खबरें सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने चेतावनी जारी की थी। रूसी अधिकारियों के समक्ष भी मामला उठाया गया था। रूसी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि उनके यहां सेना में भारतीयों का कतई इस्तेमाल न हो। भारत अनेक बार युद्ध की खिलाफत कर चुका है। रूस में अगर जवानों की कमी होने लगी है, तो उसे युद्ध से पीछे हटना चाहिए। किसी भी अन्य देश के जवानों के बल पर युद्ध जारी रखना अनैतिकता, बर्बरता और जघन्य युद्ध अपराध से कम नहीं है। यूक्रेन-रूस युद्ध में शामिल भारतीयों की संख्या भले नगण्य हो, पर विश्व स्तर पर ऐसी किसी भी भर्ती साजिश को नाकाम करने की दिशा में भारत को पुख्ता कोशिशें करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत के मामले में अभियोजन से छूट नहीं है। इसके बाद सांसदों के विशेष अधिकार पर बहस छिड़ने के साथ ही 19 मई, 1949 को संविधान सभा में सांसदों के विशेषाधिकार पर हुई बहस प्रासंगिक हो गई है।

सांसदों के अधिकारों की तालिका बनाइए

यहां स्कैन करें

एच वी कामथ | वरिष्ठ राजनेता

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुच्छेद 85 के खंड(3) में ''तब तक सांसदों के विशेषाधिकार वे ही होंगे, जो इस विधान के प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं'' के स्थान पर ये शब्द रखे जाएं- ''तब तक वे ही होंगे, जो इस विधान के प्रारंभ होने से पूर्व भारतीय अधिराज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त हैं।''

श्रीमान विभिन्न विधानों का मुझे उतना विस्तृत अथवा परिमार्जित ज्ञान नहीं है, जितना डॉक्टर आंबेडकर को है, परंतु इन विधानों के अपने अल्पज्ञान पर विश्वास करते हुए मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यह अपने रूप की पहली ही मिसाल है, जहां एक स्वतंत्र देश के विधान में दूसरे राज्य के विधान में आए हुए प्रावधानों का उल्लेख किया है। ऐसा करने के लिए मुझे कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है। यह हो सकता है कि स्वतंत्र भारत की संसद के सदस्यों को जो अधिकार तथा विशेषाधिकार हम प्रदान करना चाहते हैं, वे ठीक उसी प्रकार के अथवा न्यूनाधिक रूप में वे ही हों, जो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के सदस्यों को प्राप्त हैं, परंतु श्रीमान, क्या अति विनम्रतापूर्वक मैं यह पूछ सकता हूं कि जब हम अपना निजी विधान बना रहे हैं, तो क्या यह आवश्यक अथवा वांछनीय है कि हम किसी अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दें कि इस विषय संबंधी प्रावधान इंग्लैंड की पार्लियामेंट के प्रावधानों के अनुसार होंगे?

इस प्रस्ताव के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि यूनाइटेड किंगडम का उल्लेख करने से हमारे विधान अथवा हमारे राज्य के गौरव में कोई कमी नहीं आती है और फिर इस तर्क द्वारा इस बात की और भी पुष्टि की जा सकती है कि अब हमने यह घोषणा कर दी है कि भारत राष्ट्रसंघ का पूरा सदस्य है, इसलिए अब इंग्लैंड की पार्लियामेंट का हवाला देने में कोई आपत्ति या रुकावट नहीं होनी चाहिए। चाहे वह अपमानजनक न हो अथवा विधान की प्रतिष्ठा को कम न करता हो, परंतु क्या सभा के गंभीर विचारार्थ मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या वही विधान की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है? हम यह कहते हैं कि अमुक-अमुक बातें वैसी ही होनी चाहिए, जैसी कि यूनाइटेड किंगडम अथवा अमेरिका में हैं। किसी अन्य देश से कोई बात लेकर अपने विधान में उल्लेख के रूप में उसका समावेश करने की अपेक्षा क्या यह बराबर तथा अधिक आनंददायक नहीं होगा कि हम अपनी ही पूर्वोक्तियों अथवा अपनी भारतीय परंपराओं पर ही विश्वास करें?

क्या यहां यह कहना पर्याप्त नहीं है कि यहां अपने देश में संसद सदस्यों के अधिकार, विशेषाधिकार तथा विमुक्तियां वही होंगी, जो इस संविधान के प्रारंभ के पहले विधान परिषद् या अधिराज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त रही हैं? वैयक्तिक रूप में मैं यह समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा होगा। मैं यह आशा करने का साहस करता हूं कि इस सभा में मेरे माननीय मित्रों का झुकाव इसी विचार की ओर होगा कि यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण देने की अपेक्षा जो कुछ परंपरा हमने अपने यहां स्थापित कर रखी है, उस पर निर्भर होना ही अच्छा है। वास्तव में, कोई भी व्यक्ति इस तथ्य पर आपत्ति नहीं करेगा कि आज जो विशेषाधिकार और विमुक्तियां हमको यहां प्राप्त हैं, वे किसी रूप में भी यूनाइटेड किंगडम की लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों तथा विमुक्तियों से निम्न प्रकार की अथवा उनसे बदतर हैं।

यह बात भी सच है कि हममें से अनेक व्यक्ति यह भी नहीं जानते हैं कि वहां की लोकसभा के सदस्यों के क्या-क्या विशेषधिकार हैं? यह हम भली प्रकार जानते हैं कि इस समय हमारे विशेषाधिकार क्या हैं? अतः श्रीमान, अन्य देशों में प्रचलित प्रथाओं पर विश्वास करने की अपेक्षा अपने निजी पुष्ट आधार पर खड़े होना ही अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सभा के विचारार्थ और स्वीकारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

...मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेने का अर्थ विशेषाधिकारों के न होने से नहीं है। मैं यह स्मरण कराऊंगा कि कार्यप्रणाली के नियमों के अंतर्गत, जिनको इस सभा ने विधानमंडल के रूप में बैठकर प्रयोगात्मक रूप से अंगीकार किया है, मगर एक विशेषाधिकार समिति होगी, जो इस विषय पर विचार करेगी और सभा के विभिन्न विशेषाधिकारों को परिभाषित करेगी।

(संविधान सभा में दिए गए उद्बोधन से)

आमने-सामने

क्या आप अधिकार से वंचित रहना चाहते हैं

यहां स्कैन करें

अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर | वरिष्ठ राजनेता

महोदय, इस अनुच्छेद पर, जिस रूप में वह है, दो आपत्तियां उठाई गई हैं। एक भावना पर आश्रित है और दूसरी, किसी अन्य राज्य के सदन के उन विशेषाधिकारों के उल्लेख करने के औचित्य पर, जिनसे सामान्य नागरिक तथा यहां के संसद सदस्य संभवतः परिचित नहीं हैं ...यह सबको विदित है कि सबसे अधिक विस्तृत विशेषाधिकारों का प्रयोग इंग्लैंड के संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। अभी निर्मित भारतीय विधान-मंडल के वर्तमान विशेषाधिकारों के समान ही यदि विशेषाधिकार रखे जाएं, तो फल यह होगा कि सदन की अवज्ञा करने पर भी किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकेगा।

...ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त संघ अधिनियम में तथा कनाडा के अधिनियम में विस्तृत पदावली के कारण, दोनों स्थानों की संसद को वे ही अधिकार हैं, जो इंग्लैंड की संसद को प्राप्त हैं, अतः उनको अवज्ञा के लिए दंड देने का अधिकार है। क्या आप स्वयं को इस अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? प्रश्न तो यह है।

मैं अब दूसरी आपत्ति पर विचार करूंगा। यदि आपके पास संक्षिप्त रूप में समस्त विशेषाधिकारों की तालिका बनाने का समय तथा अवकाश है, तो यह तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि इस सभा के विधायी पक्ष की ओर अध्यक्ष द्वारा निर्मित समिति ने तब तक (विशेषाधिकार) तालिका बनाना बहुत ही कठिन समझा, ...इस प्रयोजन के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था, अतः समिति इस विषय में अध्यक्ष को कोई प्रभावी मंत्रणा न दे सकी। ...ऐसे हालात में मैं निवेदन करता हूं कि मर्यादा के विरुद्ध होने की कोई बात नहीं है। ...हिंदी के साथ-साथ कुछ समय के लिए हम अपना विधान अंग्रेजी में रख रहे हैं, तो इंग्लैंड के विशेषाधिकारों के उल्लेख पर आपत्ति क्यों?

दूसरी बात यह है कि विशेषाधिकारों की सूची बनाने के लिए उचित तंत्र की स्थापना करने में संसद के आगे कोई रुकावट नहीं है। इस अनुच्छेद में इस बात के लिए विस्तृत क्षेत्र हैं। अन्य बातों में संसद-सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियां वही होंगी, जो संसद समय-समय पर विधि द्वारा परिभाषित करेगी और वे जब तक परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी, जो इस संविधान के प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद में बस यही कहा गया है। यह आपके स्वविवेक में किसी रूप से रुकावट नहीं डालता है। आप विशेषाधिकारों को बढ़ा सकते हैं, उनको घटा सकते हैं तथा अन्य प्रकार के विशेषाधिकार रख सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का उल्लेख किए बिना आप स्वयं अपने विशेषाधिकार तय कर सकते हैं। ...केवल अस्थायी रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों को इस सदन पर लागू किया गया है। मर्यादा के विरुद्ध होने से कोसों दूर रहकर इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है...। अतः खंड (3) के शब्दों में कोई बात मर्यादा के विरुद्ध नहीं है। इस प्रथा का अनुसरण लाभदायक रूप में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा अन्य देशों में हुआ है और उससे अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तथा हरेक प्रकार से सदन को सर्वशक्ति प्राप्त हो गई है।

जब हम अंग्रेजी भाषा ग्रहण कर रहे हैं तथा जब हम उन वैधानिक पदों का प्रयोग कर रहे हैं, जो इंग्लैंड में प्रचलित हैं, तो हमें इस बात को भी ग्रहण करने से नहीं कतराना चाहिए। आप यह कह रहे हैं कि यदि हम यह कहें कि विशेषाधिकार वे ही होंगे, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं, तो इसमें गुलामी की बू है, यह दासत्व का चिह्न है। पर यह बात कोसों दूर है। आज इंग्लैंड की संसद ग्रेट ब्रिटेन, अधिराज्यों तथा अन्य राज्यों पर आधिपत्य जमाए हुए है। यह कहना कि आप उतने ही महान हैं, जितना कि ग्रेट ब्रिटेन, तो यह कोई निम्न भावना का संकेत नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान की पुष्टि करना है तथा अपनी संसद की सर्वशक्ति की भी पुष्टि करना है। अतः श्रीमान, मैं निवेदन करता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के उल्लेख पर जो आपत्ति की गई है, उसमें बिल्कुल बल नहीं है। इन हालात में यह अनुच्छेद ब्रिटेन के प्रति दासत्व, गुलामी तथा भृत्यभाव की भावना के अधीन निर्माण किए जाने से कोसों दूर रहकर आत्म-पुष्टि की भावना से निर्मित किया गया है और इस भावना की पुष्टि के लिए बनाया गया है कि हमारा देश तथा हमारी संसद उतनी ही महान है, जितनी ग्रेट ब्रिटेन की संसद।

(संविधान सभा में दिए गए उद्बोधन से)

कश्मीर की वादियों में चालीस साल बाद चैन से चुनावी सभा

यहां स्कैन करें

अश्वनी कुमार | वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की पूरे कश्मीर में चर्चा है। लोग याद कर रहे हैं कि पिछले 40 साल में पहली बार ऐसी चुनावी रैली हुई है और इसे कश्मीर में ऐतिहासिक माना जा रहा है। कश्मीर के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1983 की इकबाल पार्क रैली के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही रैली है, जो शांतिपूर्ण रही है।

लोग याद कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जैसे यहां के लोगों से जुड़कर आकर्षित करती थीं, ठीक वैसी ही कोशिश नरेंद्र मोदी ने भी की है। प्रधानमंत्री ने मधुमक्खी पालन में कमाल करने वाले पुलवामा के नाजिम नजीर के साथ सेल्फी लेकर लोगों के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश की है, इसकी चर्चा घाटी में हो रही है।

बहरहाल, इस रैली के ऐतिहासिक होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 37 ए को खत्म किए जाने के बाद प्रधानमंत्री की घाटी में यह पहली रैली थी। दूसरा कारण यह है कि अलगाववादियों और पाकिस्तान को वह बताना चाहते थे कि नया कश्मीर बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री कहीं भी रैली कर सकते हैं। तीसरा कारण, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों- मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यहां जनसभा की थी, पर उस दौरान बम धमाके और काफी खून-खराबा होता था। अलगाववादी नेताओं और आतंकियों के आह्वान पर कश्मीर में हड़ताल, कर्फ्यू, सार्वजनिक परिवहन के ठप होने का आलम रहता था। तब जान-बूझकर घाटी में बम धमाके भी करवाए जाते थे, पर इस बार न कोई हड़ताल, न बम धमाके, न चक्का जाम और न ही इंटरनेट बंद किया गया।

प्रधानमंत्री के 27 मिनट के भाषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वे साढ़े चार मिनट थे, जब प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर बैंक के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले तक जम्मू-कश्मीर बैंक डूब रहा था, लेकिन सरकार की नई नीति की वजह से बैंक डूबने से बच गया। अगर लोगों के हजारों करोड़ रुपये डूब जाते, तो क्या होता? उन्होंने जम्मू-कश्मीर बैंक की भर्ती में हुई हेराफेरी के बारे में भी लोगों को बताया। जाहिर है, प्रधानमंत्री यह संदेश देना चाहते थे कि कश्मीर में दशकों से चली आ रही रिश्वतखोरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री को अच्छे से पता है कि जम्मू-कश्मीर के ज्यादातर लोगों के पैसे इसी बैंक में जमा हैं, अतः लोगों के बीच अपने बैंक और अपने पैसे को लेकर खास चर्चा है, तो क्या इसका फायदा भाजपा को होगा?

जम्मू-कश्मीर के जानकार लोग यह याद कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जैसे यहां के लोगों से जुड़कर आकर्षित करती थीं, ठीक वैसी ही कारगर कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।

हालांकि, कुछ लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने या स्थानीय चुनाव संबंधी घोषणा करेंगे? पर शायद अभी इन मुद्दों पर केंद्र सरकार ने अपना मन नहीं बनाया है। यहां इस बात की चर्चा है कि सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। पाकिस्तान की हालत को देखकर यहां लोग भी समझ गए हैं कि अनुच्छेद 370 की बहाली नामुमकिन है और कुछ ही समूह या दल हैं, जो कश्मीरियों को अब भी बरगलाने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है और सरकार इस विषय को अब छूने को बिल्कुल तैयार नहीं है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से रैली में लोगों का हुजूम उमड़ा है, हाल ही में जैसे गुज्जर बकरवालों और पहाड़ियों को आरक्षण मिला है, उससे भाजपा को लाभ होगा। पीडीपी के पूर्व सांसद और उनकी पत्नी सफीना बेग का प्रधानमंत्री की रैली में होना साफ बताता कि पहाड़ी लोग भाजपा के साथ हैं।

प्रधानमंत्री ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम लिए बिना परिवारवाद के प्रति लोगों को सावधान किया है। लगातार परिवारवादी शासन से हुए नुकसान का लोगों को भी अंदाजा है। लोग मजबूत विकल्प की तलाश में हैं और भाजपा एक विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रही है। जाहिर है, कश्मीर में भाजपा की मजबूती और जमीनी अमन-चैन के बीच शुरू हुई तरक्की का लाभ पूरे देश में भी पार्टी को मिल सकता है।

लोग एक और बात पर खास गौर कर रहे हैं, कश्मीर में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शंकराचार्य मंदिर और हजरतबल श्राइन, दोनों को समान महत्व दिया है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि उनके लिए हिंदू, मुस्लिम एक समान हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 09 मार्च, 1949

पड़ोसी नेपाल

नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। उसके साथ दीर्घकाल से भारत के घनिष्ठ सम्बन्ध चले आते हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं। खून का रिश्ता है। नेपाली गोरखा सैनिकों को भारत की सेना में विशेष स्थान मिला हुआ है। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद नेपाल के साथ उसके सम्बन्ध और भी प्रगाढ़ हुए हैं।

भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से भारत और नेपाल के बीच मित्रता के अलावा और किसी प्रकार के सम्बन्धों की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आगे चलकर यही मित्रता की भावना दोनों के बीच पार्थक्य की समस्त दीवारों को गिरा दे सकती है। भारत और नेपाल संयुक्त हो सकते हैं। यह हमारी ही कल्पना नहीं है। स्वयं नेपाल के लोग भी इसी दिशा में सोचते मालूम देते हैं। दरभंगा की एक खबर के अनुसार नेपाल की राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा है कि संयुक्त और सुदृढ़ भारत का निर्माण करने के प्रयास में नेपाल को शामिल होना चाहिए। नेपाल बहुत समय तक अलग और एकान्त में रहा। अब उसे अपने आत्म-विकास के लिए भी व्यापक दायरे में आना चाहिए।

नेपाल के विषय में यदा-कदा जो समाचार अखबारों में प्रकाशित होते रहते हैं, उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि नेपाल के शासन में समय के अनुसार अभी आवश्यक मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है। मध्ययुगीन निरंकुशता का वहां वैसा ही बोलबाला है। लोगों की नागरिक आजादी छिनी हुई है। नेपाल के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को अपनी मातृभूमि से बाहर भारत की भूमि में रहते हुए जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रजा की आवाज को शासन कठोरतापूर्वक दबा देता है। पिछले दिनों राजनीतिक कारणों पर नेपाल में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ को कठोर और लम्बी सजायें दी गई हैं। नेपाल के शासन के लिए नागरिक स्वतन्त्रता का यह दमन शोभास्पद नहीं कहा जा सकता। भारत की स्वतन्त्रता के बाद नेपाल में भी जनता की आकांक्षा जागृत हो चुकी है। स्वशासन की उसकी मांग को दमन के जरिये अधिक काल तक दबाया नहीं जा सकेगा।

मनसा वाचा कर्मणा

अपना-अपना तरीका

अपनी शराफत और ईमानदारी के लिए ख्यात एक समुराई एक जेन भिक्षु के पास अपनी जिज्ञासा लेकर पहुंचा। भिक्षु उस समय प्रार्थना कर रहे थे। जब वह प्रार्थना से उठे, तो समुराई ने उनसे पूछा, 'मैंने अनेक कमजोर लोगों की रक्षा की, फिर भी इतनी हीनता क्यों महसूस होती है? फिर आपको यूं ध्यानस्थ देखकर मुझे क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी निरर्थक है?'

भिक्षु ने समुराई से कहा, 'प्रतीक्षा करो, मुझे पहले उन लोगों से मिलना होगा, जो मुझसे मिलने आए हैं, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा।' मठ के बाग में बैठे-बैठे समुराई पूरे दिन लोगों को आते-जाते देखता रहा। उसने गौर किया कि भिक्षु ने समान धैर्य और उज्ज्वल मुस्कान के साथ उन सबका स्वागत किया। जब रात हो गई और सभी आगंतुक चले गए, तब भिक्षु समुराई को एक कक्ष में ले गए, जिसके गवाक्ष से पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था, वहां गहन शांति छाई थी। भिक्षु ने समुराई से पूछा, 'तुमने चांद को देखा, बेहद खूबसूरत है न? कल सुबह सूरज उगेगा। सूर्य की रोशनी इसके प्रकाश से कई गुना चमकदार होगी, उसमें तमाम चीजें साफ-साफ दिखेंगी। मैंने इन दोनों पर वर्षों तक मनन किया, और कभी नहीं पाया कि चांद ने कहा हो : मैं सूरज-सा क्यों नहीं चमकता? क्या इसलिए कि मैं हीन हूं?'

समुराई ने कहा, 'बिल्कुल नहीं! चांद व सूरज, दोनों अलग हैं, दोनों की अपनी खूबसूरती है। आप उनकी तुलना नहीं कर सकते।' जेन भिक्षु ने मुस्कराकर कहा, 'तुम्हें तो उत्तर पता है। हम दोनों दो अलग मनुष्य हैं। दोनों अपने-अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए अपने-अपने रास्ते से हमें इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए।'

पाउलो कोएल्हो

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

जिस भाषा (संस्कृत) में गार्गी, मैत्रेयी, अपाला और लोपामुद्रा जैसी महिला विभूतियों ने ज्ञान का अमर अवदान दिया हो, उसके अध्ययन-अध्यापन में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक होनी ही चाहिए।

मां, माटी, मानुष, तीनों का अपमान

'मां, माटी और मानुष' के नारे के साथ पश्चिम बंगाल में सत्तासीन हुई तृणमूल कांग्रेस के राज में मां, माटी और मानुष, तीनों का अनवरत अपमान हुआ है। मां काली को प्रथम देवी के रूप में पूजने वाली इस संस्कृति में महिलाओं की दयनीय दशा संदेशखाली से उजागर हुई है। ऐसा लगता है कि किसानों और महिलाओं के साथ जो अत्याचार पूर्व की वामपंथी सरकार में किया जाता था, वह तृणमूल कांग्रेस के राज में भी बदस्तूर जारी है। माफिया और गुंडों को सरकारी संरक्षण किस हद तक मिला हुआ है, इस बात का अंदाजा इससे ही हो जाता है कि संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख को पकड़ने में पश्चिम बंगाल की पुलिस को करीब दो महीने लग गए।

संदेशखाली का बर्बर सच दुनिया के सामने तब आया, जब यहां की महिलाओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। झाड़ू और लाठी हाथों में लेकर ये महिलाएं इस 'भद्र देश' में लंबे समय से किए जा रहे अपने जघन्य दैहिक शोषण के विरुद्ध प्रदर्शन करने सड़क पर उतर आईं। उनका कहना था कि संदेशखाली में शायद ही ऐसी कोई महिला है, जो शाहजहां शेख के जुल्म का शिकार न बनी हो। पुलिस उनकी सुन नहीं रही थी, क्योंकि शिकायत करने पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिसकर्मी उल्टे यही कहते कि जाकर शाहजहां से समझौता कर लो। इस प्रकार राज्य संरक्षित गुंडों के आतंक के कारण ये महिलाएं अपनी पीड़ा जज्ब किए बैठी थीं। जाहिर है, अब जो भंडाफोड़ हुआ है, उसने पश्चिम बंगाल में राज्य संरक्षित गुंडों द्वारा किए जा रहे आतंक को बेपरदा कर दिया है। इससे यह भी पता चलता है कि यह राज्य किस हद तक अराजक हो गया है। ऐसे में, सभी राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शासन, पुलिस और विशेष रूप से महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का दायित्व है कि वे यह पता करें कि राज्य में कहीं और संदेशखाली तो नहीं? इस घटनाक्रम का यह भी संदेश है कि स्त्री-सम्मान किसी एक राजनीतिक संगठन का दायित्व नहीं, बल्कि सभी की जिम्मेदारी है।

स्पष्ट है, पुलिस, प्रशासन और राज्य को अपना हित साधने के बजाय जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अब दलगत राजनीति, भेदभाव और व्यक्तिगत लाभ-हानि को छोड़कर पूरे समाज को साथ लाने की जरूरत है, ताकि ऐसा तीव्र प्रतिरोध खड़ा किया जा सके कि देश में कोई इलाका संदेशखाली न बन सके। अगर कोई शाहजहां शेख स्त्रियों के साथ बर्बरता करता पकड़ा जाए, तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यही ऐसे मामलों का उचित समाधान है।

वंदना गांधी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

संदेशखाली

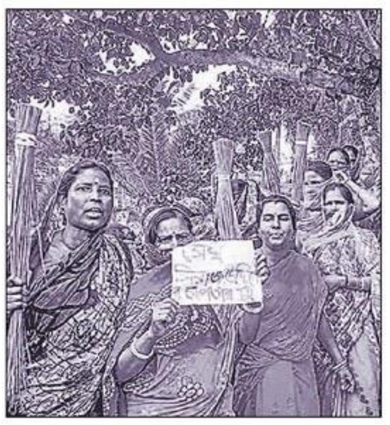

राजनीति के तहत इसे तूल दिया गया

संदेशखाली में जो हुआ है, वह बहुत ही शर्मनाक है। इस मामले में जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है, जरूर की जानी चाहिए। दोषी कोई भी हो, उसे कानून के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए और अदालत जो भी फैसला सुनाए, उस पर तत्काल अमल होना चाहिए। मगर क्या यह भी सच नहीं कि संदेशखाली को राजनीतिक वजहों से अधिक तूल दिया गया है? क्या महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण सिर्फ पश्चिम बंगाल में होता है? हाल-फिलहाल ही ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मणिपुर में दो महिलाओं को सरेआम प्रताड़ित किया गया। उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, यह अब तक पता नहीं चल सका है। इसी तरह, देश की महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था और विरोधस्वरूप अपने ओलंपिक पदक भी लौटा दिए थे, लेकिन आरोपी पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई? संदेशखाली क्या, देश के किसी भी कोने में अगर महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है या उनका शोषण होता है, तो वह अक्षम्य अपराध है, लेकिन हमने यह भी देखा है कि कैसे कुछ खास मामलों पर ही कार्रवाई की गई, बाकी को नजरंदाज किया गया, क्योंकि वहां से राजनीतिक हित सधते नहीं दिख रहे थे?

अपने देश के धर्मग्रंथों में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस पर व्यावहारिक अमल नहीं होता। अगर हम महिलाओं के प्रति संवेदनशील होते, तो भारत में बलात्कार के रोजाना 86 मामले दर्ज नहीं होते, यानी हर घंटे तकरीबन चार महिलाओं की अस्मत नहीं लुटती। ये तो वे मामले हैं, जो पुलिस फाइलों में दर्ज हुए हैं। ज्यादातर मामले तो परिवार-समाज के दबाव के कारण थानों तक पहुंच ही नहीं पाते। माना जाता है कि ऐसे मामलों की संख्या दर्ज मामलों से बहुत अधिक है। देश में बेटी बचाने की बात तो खूब की जा रही है, लेकिन सियासी दल उसी राज्य में मुखर होते हैं, जहां उन्हें अपनी राजनीतिक रोटी पकने की उम्मीद होती है।

एक आदर्श समाज वही है, जिसमें कोई शोषणमूलक व्यवस्था न हो। भारत इस तरह का समाज रच सकता है, लेकिन संभवतः राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में यह नहीं है। वे सिर्फ चुनावी लाभ के लिए मुद्दे उठाते और गिराते हैं। उनके लिए चुनाव जीतना ही सब कुछ है, इसलिए वे बाहुबली को भी खुली छूट दे देते हैं। ऐसे में, जनता यदि जागरूक हो जाए, तो यह व्यवस्था खत्म हो सकती है। मगर क्या हाल-फिलहाल ऐसा हो सकेगा? ऐसा लगता नहीं है, खासकर सियासी दलों के रुख को देखकर।

मोहित, टिप्पणीकार

जानें ईवी या आईसीई कार में किफायत का सच

जब से इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन शुरू हुआ है, तब से एक और बहस शुरू हो गई है कि किफायती वाहन कौन सा है! यानी ईवी या पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों में सच में सस्ता कौन पड़ता है? बता दें कि कुछ ईवी कारों की कीमतों में हुई कटौती से बचत के समीकरण भी बदले हैं। यहां पेश है एक विश्लेषण

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपने टिएगो और नेक्सॉन की कीमतें क्रमशः 70 हजार व 1.2 लाख रुपए तक कम कर दी हैं। टिएगो ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) की कीमत अब एक्स शोरूम 7.99 लाख रुपए होगी, जबकि नेक्सॉन 14.49 लाख रुपए में आएगी। कीमतें कम होने के बाद टिएगो भारत में दूसरी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसके आगे केवल एमजी कॉमेट है, जिसकी कीमत 6.99 लाख रुपए है। कीमतें कम होने पर ईवी की चाहत रखने वाले खरीदारों के लिए ये और सुलभ होंगी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में ईवी के महंगे दाम एक बड़ी बाधा रहे हैं। लेकिन कार की किफायत सिर्फ कीमत से ही नहीं निर्धारित होती। वहीं ईवी और जीवाश्म ईंधन की कारों (आईसीई कारें) की कीमत में जो अंतर है, ईवी के दामों में कटौती से उसकी भरपाई होने की समयावधि भी कम हुई है। कई बातें हैं, जिनके आधार पर बचत की इस गणित को समझा जा सकता है:

ऐसे समझें किफायत का गणित

इस संदर्भ में यह देखना जरूरी है कि इन दोनों प्रकार की कारों में लंबी अवधि में ईंधन और रखरखाव पर क्या खर्च होता है? एक पहले के विश्लेषण के अनुसार प्रतिदिन 30 किलोमीटर दौड़ने वाली ईवी कार साढ़े छह साल में किफायत देने लगेगी। यहां इसे टाटा टिएगो एक्सटीए (आईसीई यानी जीवाश्म ईंधन की कार) के साथ टाटा टिएगो ईवी एक्सटी (मीडियम रेंज-250 किलोमीटर) की तुलना से समझने की कोशिश है। टिएगो एक्सटी (ईवी) की कीमत 8.99 लाख रुपए है, जबकि टिएगो एक्सटीए 6.95 लाख रुपए में आ सकती है। वहीं ईवी मॉडल पर इंश्योरेंस का शुल्क भी ज्यादा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्ज अपेक्षाकृत कम है। अगर रनिंग कॉस्ट को देखें, तो ईवी पर होने वाला खर्च एक समयावधि के बाद कम होता नजर आता है। यानी एक लाख किलोमीटर या 6 साल के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। एक्सटीए मॉडल में इंश्योरेंस का शुल्क, सर्विस और ईंधन का खर्च प्रति 50 हजार किलोमीटर पर 3.73 लाख रुपए है, जबकि इसी मामले में ईवी में 1.06 लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसे में रनिंग कॉस्ट के मामले में ईवी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले फिट बैठती है।

अब लाभ मिलेगा जल्दी

यह सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक कारें जीवाश्म ईंधन की कारों की तुलना में पर्यावरण के लिए अच्छी तो होती हैं, लेकिन महंगी होती हैं। लेकिन कीमत के अंतर की भरपाई वक्त के साथ ईवी कर देती है। लेकिन यह कितना वक्त इसकी भरपाई में लेगी, इसमें भी अब पहले की तुलना में सुधार हुआ है। जैसे पहले के एक लेख से नेक्सॉन ईवी का उदाहरण लें, तो हर दिन 40 किलोमीटर चलने पर इसे 4.2 साल में किफायत देने लायक पाया गया था। जबकि टिएगो ईवी इतनी ही दूरी तय करने में 3.42 साल में किफायती हो जाती है।

इस तरह का अंतर कई बातों पर निर्भर करता है। मसलन टिएगो ईवी की एकमुश्त कीमत नेक्सॉन ईवी के मुकाबले कम होती है, जिससे शुरुआती निवेश आसान होता है। ऐसे में जब वर्तमान में नेक्सॉन और टिएगो के दामों में कटौती हुई है, तो यह भरपाई होने की अवधि पर भी दिखाई देगा। यानी भरपाई भी जल्दी होगी।

दूसरा टिएगो ईवी का रनिंग कॉस्ट तो कम है ही, साथ ही इसमें बैटरी बदलने का खर्च भी कम होता है और इसमें आठ साल या 160000 किमी के बाद बैटरी बदलने की जरूरत होती है।

इंश्योरेंस या अन्य खर्च

आईसीई कारों के मुकाबले ईवी का इंश्योरेंस खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि ईवी में बैटरी और मरम्मत की दूसरी जरूरतें सामान्य नहीं होती हैं। ईवी की मरम्मत करने के लिए एडवांस तकनीक की जरूरत होती है, जो आमतौर पर महंगी होती है। इसमें बैटरी और दूसरी इलेक्ट्रिकल चीजों को बदलने का खर्च भी ज्यादा होता है। हालांकि ईवी में इंश्योरेंस की प्रक्रिया दूसरी गाड़ियों के मुकाबले अलग नहीं होती है। इरडा ने 2022-23 में ईवी पर इंश्योरेंस खर्च में 15 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे इसकी कीमत और दूसरे खर्च कम हो गए। यह भी समझना होगा कि जितनी ज्यादा संख्या में ईवी सड़क पर दौड़ेंगी, उतना ही उनकी मरम्मत का खर्च कम होगा।

चार्जिंग की समस्या भी हो रही दूर

ईवी में चार्जिंग महत्वपूर्ण होती है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों पर प्रति किलोवॉट चार्जिंग का शुल्क 5 से 15 रुपए होता है। हालांकि फास्ट चार्जिंग की सेवा लेने पर शुल्क ज्यादा हो जाता है। जबकि अगर आप घर में इसे चार्ज करते हैं, तो यही खर्च 2 से 9 रुपये प्रति किलोवॉट हो जाता है। होम चार्जिंग सस्ती पड़ती है, क्योंकि बाहर चार्ज करवाने पर कमर्शियल चार्ज लगता है। इसके अलावा हो सकता है कि चार्जिंग स्टेशन पर पार्किंग और सबस्क्रिप्शन शुल्क भी लिया जाए। इस तरह के चार्जिंग स्टेशन की संख्या देश में बढ़ रही है।

यह भी दें ध्यान

- अधिकतर अफोर्डेबल ईवी की रेंज कम होती है यानी बैटरी फुल चार्ज होने पर भी ये कम दूरी तय करती हैं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए ईवी उपयोगी नहीं।
- 8 साल या 1.60 लाख किलोमीटर चलने के बाद ईवी की बैटरी बदलनी पड़ती है, जिसकी लागत करीब 4.5 लाख रुपए होती है।

mint

> ईवी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा उपयोगी हैं। यह महंगी हैं, परंतु कुछ कंपनियां इसे पेट्रोल कारों के रेट में ले आई हैं। टाटा जैसी कंपनी ने तो पेट्रोल कार के रेट में टिएगो पेश कर दी है। इसकी डेढ़ लाख रुपए कीमत कम कर दी है। रही बात बैटरी की, तो कंपनियां इस पर भी सात से आठ साल तक की गारंटी दे रही हैं। बैटरी भी लिथियम जैसी हाईब्रिड होती हैं। कंपनियां बैटरी की रिप्लेसमेंट की बात करती हैं। परंतु सीएनजी या पेट्रोल के मुकाबले ग्राहक के लिहाज से रोज की रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। अगर एक लाख किलोमीटर ईवी चलाई, तो एक रुपये खर्च आता है, प्रति किलोमीटर और पेट्रोल गाड़ी में यही खर्च 8 रुपए प्रति किलोमीटर हो जाता है।
>
> – **अशोक वर्मा**, ऑटो एक्सपर्ट

सीएनजी क्यों नहीं?

- सीएनजी कारों में बूट स्पेस का मुद्दा अकसर ज्यादा दूरी तय करने वालों के लिए परेशानी बनेगा। सामान के लिए कार की छत पर लगाया गया रूफ कैरियर पैसे और माइलेज पर असर कर सकता है। साथ ही सीएनजी फिलिंग स्टेशंन घर से दूर होने पर भी परेशानी आती है, और फिलिंग स्टेशन पर लगी लंबी कतारें भी परेशान कर सकती हैं।
- अगर रोज की रनिंग सीमित है, तो कंपनी फिटेड सीएनजी किट के लिए दिए जाने वाले अतिरिक्त पैसे की भरपाई यानी बचत भी काफी लंबे समय बाद शुरू होती है।

गैजेट्स

फीचर से लबरेज हैं ये फोन

हाल ही में सैमसंग और लावा ने अपने नए फोन बाजार में उतारे हैं। वाजिब कीमत पर कई फीचर्स और अच्छी क्षमता के कैमरे वाले ये फोन युवाओं को पसंद आएंगे।

लावा का ब्लेज कर्व्ड 5जी

लावा ने भारत में अपना ब्लेज सीरीज का सबसे उम्दा फोन पेश कर दिया है। यह फोन दो वेरिएंट 8 जीबी+128 जीबी और 8 जीबी+ 256 जीबी में बाजार में उतारा गया है। इसकी बिक्री 11 मार्च से अमेजन और लावा स्टोर पर शुरू होगी। फोन दो रंगों -ग्रीडियन और आइरन ग्लास -में उपलब्ध है।

क्या है खास : कंपनी 6.67 कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले की पेशकश लेकर आई है। फोन में कंपनी 8 जीबी एलपीडीडीआर5 रैम और 8 जीबी वर्चुअल रैम दे रही है। यानी कुल रैम 16 जीबी तक की मिल रही है। 256 जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में मीडयाटेक डाइमेंसिटी 7050 चिपसेट प्रोसेसर है।

कैमरा : इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिल रहे हैं। इनमें 64 मेगापिक्सल के ईआईएस सोनी सेंसर के साथ एक 8 एमपी का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और एक 2 मेगा पिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। 32 एमपी का फ्रंट कैमरा है। बैटरी 5000 एमएएच की है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इन-डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर वाला यह फोन एंड्रॉयड 13 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के भी कई फीचर्स हैं।

कीमत : 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये, वहीं 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है।

गैलेक्सी एफ15 5जी

सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज के नए फोन सैमसंग गैलेक्सी एफ15 5जी को भारत में हाल ही में पेश किया है। यह हालिया फोन 4 जीबी +128 जीबी और 6 जीबी+ 128 जीबी के दो विकल्पों में आता है।

क्या है खास : फोन में 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। फोन 6 जीबी तक की रैम और 128 जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6100 प्लस चिपसेट का प्रोसेसर है।

कैमरा : एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे, जिनमें 50 एमपी के मुख्य लेंस के साथ एक 5 एमपी का अल्ट्रा वाइड ऐंगल लेंस और एक 2 एमपी का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 13 एमपी का फ्रंट कैमरा है। फोन एंड्रॉयड 14 पर आधारित है, और वनयूआई 6.0 पर काम करता है।

इस फोन को कंपनी 4 जेनरेशन तक एंड्रॉयड अपडेट और 5 साल तक सिक्योरटी अपडेट देगी।

कीमत : 6 जीबी रैम वाले वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये।

फीचर डेस्क

नई गाड़ी

हुंडई लाई वेन्यू का नया टर्बो वेरिएंट

दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी हुंडई ने अपनी लोकप्रिय कार वेन्यू का एक और नया अवतार पेश किया है। इसमें नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। आइए जानते हैं

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय एसयूवी कार वेन्यू का एक नया वेरिएंट पेश किया है। इसे 'एग्जीक्यूटिव टर्बो' नाम दिया गया है। नया वेरिएंट केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ बेचा जाएगा। इसके अलावा हुंडई ने वेन्यू एस (ओ) टर्बो ट्रिम में और ज्यादा फीचर्स भी जोड़े हैं।

फीचर्स क्या हैं?

हुंडई वेन्यू एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में बाहर से, इंटीरियर में, सुरक्षा के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से, पावरट्रेन में, सुविधा और आराम के लिहाज से कई उल्लेखनीय फीचर्स जोड़े गए हैं।

एक्स्टीरियर यानी बाहर से जो जोड़ा गया है, उसमें सबसे खास है आर 16 डुअल टोन के अंदाज में पहिए, डार्क क्रोम में सामने की ओर की रेडिएटर ग्रिल, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटेना।

नए वेरिएंट में मिलने वाले तकनीकी नए फीचर्स की बात करें तो 20.32 सेंटीमीटर यानी 8.0 इंच डिस्प्ले के साथ एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। साथ में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/ एपल कार प्ले वॉइस रिकग्निशन के साथ मिलता है। कलर टीएफटी एमआईडी के साथ एक डिजिटल क्लस्टर मिलेगा।

इसके अलावा इसमें 2 सीट रिक्लाइनिंग रियर सीट, स्टोरेज के साथ ड्राइवर का आर्मरिस्ट, 60:40 में बंटी रियर सीट, सभी सवारियों के लिए समायोजित होने वाले हेडरेस्ट दिए हैं।

सुविधा के लिए रियर एअरकंडीशनर वेंट, रियर वाइपर और वॉशर मिलेंगे। स्टीयरिंग पर क्रूज कंट्रोल के साथ अन्य कंट्रोल दिए गए हैं।

वहीं सेफ्टी फीचर्स में 6 एअर बैग, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स दी गई हैं, साथ ही सीट बेल्ट लगाने की याद दिलाता फीचर यानी रिमाइंडर भी है। इस वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, डे एंड नाइट इन साइट रियर व्यू मिरर, ऑटोमेटिक हैडलैंप और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलेगा।

एस (ओ) टर्बो ट्रिम के अपडेट

साथ ही वेन्यू एस (ओ) टर्बो ट्रिम को भी अपडेट किया है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ और चालकों और सवारियों के लिए मैप लैंप जोड़े गए हैं। यह ट्रिम कप्पा 1.0आई टी जीडीआई इंजन और 6 स्पीड मैनुअल (6 एमटी) और 7 डीसीटी ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है।

वेन्यू का अपडेटेड एस (ओ) टर्बो ट्रिम 10,75,200 रुपये (6एमटी संस्करण के लिए) और 11,85,900 (7 डीसीटी संस्करण के लिए) की कीमत पर उपलब्ध है।

कैसा है पावरट्रेन

एग्जीक्यूटिव टर्बो वेरिएंट के इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.0आई-जीडीआई टर्बो इंजन मिलता है, जो 120 पीएस का पावर और 172 एनएम का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। मानक के रूप में इस इंजन को -आइडल स्टॉप एंड गो फीचर मिलता है। इससे वेरिएंट की ईंधन को लेकर कुशलता में बढ़ोतरी होती है। वेन्यू का एग्जीक्यूटिव टर्बो वेरिएंट 9,99,990 रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है।

गोविंद

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। लाभ के अवसर मिलेंगे। परिश्रम अधिक रहेगा।

वृष : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मिथुन : मन अशांत रहेगा। बातचीत में संतुलित रहें। सेहत का ध्यान रखें। संतान की सेहत में सुधार होगा। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बनेंगे।

कर्क : मन परेशान रहेगा। मन में निराशा और असंतोष रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। कार्यभार बढ़ेगा।

सिंह : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। परंतु संयत रहें। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। परंतु किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

कन्या : मन अशांत रहेगा। आत्मसंयत रहें। मानसिक शांति बनाए रखने के प्रयास करें। कारोबार में कठिनाई आ सकती है। सचेत रहें। सेहत का ध्यान रखें।

तुला : आत्मविश्वास बहुत रहेगा। परंतु मन परेशान भी हो सकता है। कारोबार में उतार-चढ़ाव भी हो सकता है। परंतु फिर भी लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं।

वृश्चिक : मन अशांत हो सकता है। संतान की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा।

धनु : पटन-पाटन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। परंतु परिश्रम अधिक रहेगा।

मकर : मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। क्रोध से बचें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता का सान्निध्य मिलेगा। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं।

कुंभ : आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा। परंतु मन परेशान भी हो सकता है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। भागदौड़ अधिक रहेगी।

मीन : मन अशांत रहेगा। संयत रहें। शैक्षिक कार्यों पर भी ध्यान दें। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। पिता से आर्थिक सहयोग मिलेगा।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

09 मार्च, शनिवार, 19, फाल्गुन (सौर) शक संवत् 1945, 26 फाल्गुन मास प्रविष्टे (पंजाब पंचांग) 2080, 27, शब्बान सन् 1445, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी (विक्रमी संवत्) सायं 06.18 बजे पश्चात अमावस्या, शतभिषा नक्षत्र रात्रि 4.56 मिनट तक पश्चात पूर्वाभाद्रपदा, सिद्ध योग रात्रि 8.32 बजे तक, विष्टि भद्रा करण, चंद्रमा कुंभ राशि में दिन-रात। **सूर्य उत्तरायण।** सूर्य दक्षिण गोल। वसंत ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10 बजकर 30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 08 बजकर 08 मिनट तक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

ध्वजा या पताका लगाने का वास्तु शास्त्र में क्या महत्व है? इसके नियम क्या हैं?
-नेहा, गोरखपुर

- ध्वज या पताका घर में या किसी भी भवन की छत पर लगाने से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता आती है। शोक व दोष का नाश होता है।
- झंडा सदैव पीला, गेरुआ, भगवा या केसरिया लगाना चाहिए।
- झंडे/पताका पर ॐ, स्वास्तिक या कोई धार्मिक श्लोक लिखा होना चाहिए।
- झंडे का आकार त्रिभुजाकार या द्वि-त्रिभुजाकार होना चाहिए।
- यथासम्भव ध्वज वायव्य कोण में लगाना चाहिए।

वर्ग पहेली : 7537

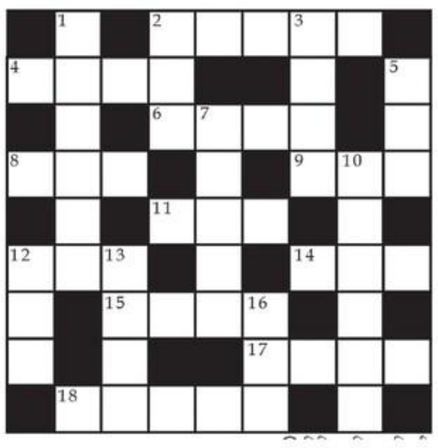

बाएं से दाएं
2. सहिष्णु; संतोषी; सहने वाला (5)
4. नक्कारे की आवाज; शोरगुल; शोहरत; बालू आदि भरकर की गई मोर्चे बंदी; धुस्स; मोर्चा; धौंसा; नगाड़ा (4)
6. एक जैसा; बराबर सतह वाला; समान तल वाला (4)
8. कन्या; लड़की; पुत्री; बेटी (3)
9. कर्णधार; तारने वाला; पार उतारने वाला (3)
11. दर्पण; शीशा (3)
12. अबोध; पुत्र; बच्चा; लड़का (3)
14. नारी; स्त्री (3)
15. लचर होने का भाव; कमजोरी; तथ्यहीनता; तर्कहीनता (4)
17. परिक्षेत्र; परिधि; भवन क्षेत्र (4)
18. फंसाना; लालच देना; लालसा जगाना; लुब्ध करना (2,3)

ऊपर से नीचे
1. जो अवसर के उपयुक्त हो; जो समय के अनुकूल हो; समयानुसार (6)
2. योग; समर्थन; संबंध; समूह; शब्द संधि (3)
3. ठंडक; सर्दी; जड़ता (4)
5. लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने वाला; अपनी ओर आकृष्ट करने वाला (3)
7. जिसमें मलाई हो; स्निग्ध (5)
10. आनंद आना; रंग में मग्न होना; (2,4)
12. रुकावट डालने वाला; विघ्नकारक (3)
13. आह भरना; कुढ़ना; बिलखना (4)
16. अपने को तप्त करना; सेंकना (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली 7536 का उत्तर

1 तं	2 दु	रु	स्ती	■	3 प	4 न	प	5 ना
■	रु	■	■	6 र	■	वी	■	ता
7 कां	प	ना	■	ह	■	8 न	ग	र
■	यो	■	9 स	म	वे	त	■	ख
10 म	ग	11 र	■	दि	■	12 म	13 र	ना
द्य	■	14 सं	फ	ल	ता	■	वा	■
15 नि	वि	दा	■	हो	■	16 त	ना	व
षे	■	य	■	ना	■	■	हो	■
17 ध	ध	क	ना	■	18 यं	था	ना	म

सुडोकू : 7521

* कठिन

				3			5	4
		4	2					
	3		4	6				
5					3		8	7
	4						6	
8	1		9					3
				5	7		3	
					9	4		
1	8			2				

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

हल : सुडोकू नं.7520

4	6	7	8	5	3	1	9	2
5	1	9	2	6	7	4	3	8
3	8	2	9	1	4	7	5	6
1	4	6	3	9	2	5	8	7
2	9	5	1	7	8	3	6	4
8	7	3	6	4	5	9	2	1
6	5	8	7	3	1	2	4	9
7	2	4	5	8	9	6	1	3
9	3	1	4	2	6	8	7	5

शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। - नेल्सन मंडेला

किसान आंदोलन के दौरान बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की टिप्पणी विचारणीय है, जो बताती है कि आंदोलन के तरीके कैसे होने चाहिए। और, अगर आंदोलन से भय पैदा हो रहा हो, तो अर्थ यही है कि यह अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है।

आंदोलन की शुचिता

किसान आंदोलन के दौरान बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसान नेताओं को जो फटकार लगाई है, वह तो उचित है ही, किसान नेताओं का यह कृत्य भी उतना ही शर्मनाक है। अदालत की यह टिप्पणी आंखें खोलने वाली है कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, वे हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में करीब 250 किसान संगठनों ने, फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी समेत 12 सूत्री मांगों के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से 13 फरवरी को 'दिल्ली चलो' अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने पर किसान हरियाणा और पंजाब की सीमा पर शंभू और खनौरी सीमाओं पर जमे हैं। ऐसे में, दोनों राज्यों की सीमाओं पर इस वक्त जैसे हालात हैं, अदालत का यह सवाल बिल्कुल तर्कसंगत है कि क्या किसान नेता अपने बच्चों को वहां भेजते? इसके अलावा, खनौरी सीमा पर पिछले माह 21 फरवरी को प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान किसान शुभकरण सिंह की मौत की अदालत द्वारा न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इस प्रकरण में पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं, जिसने 21 फरवरी को हुई घटना पर 28 फरवरी को एफआईआर दर्ज की। इस मामले में दोनों राज्यों की सरकारों का रवैया भी पल्ला झाड़ने सरीखा रहा है, शायद यही वजह है कि अदालत ने शुभकरण की मौत के मामले की जांच का जिम्मा स्वतंत्र कमेटी को सौंपा है। किसानों ने 2020-21 में भी आंदोलन किया था और तब उनकी बात सुनी भी गई थी। लेकिन अब तलवार लहराते हुए किसान जो रवैया दिखा रहे हैं, वह शांतिपूर्ण आंदोलन की परिधि में कहीं से नहीं आता। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसकी आड़ में समाजविरोधी तत्व फायदा न उठा पाएं। विरोध करने का अधिकार सबको है। कभी-कभी उचित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए आंदोलन भी जरूरी होते हैं। लेकिन विरोध की भी मर्यादा होती है। आंदोलन अगर भय उत्पन्न करे, कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए और आम जन-जीवन को अस्त-व्यस्त करे, तो इसका यही अर्थ है कि वह अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है। आंदोलन की भी शुचिता होती है, जिसका ध्यान सभी को रखना चाहिए।

उत्तर बनाम दक्षिण का पैंतरा

इतिहास बताता है कि दक्षिण भारत ने हमेशा से गांधी परिवार को समर्थन दिया है। लेकिन अब क्षेत्रीय दलों के बदलते समीकरणों के साथ जमीनी वास्तविकता बदल रही है। ऐसे में, कथित उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा भाजपा को रोक सकेगा, इसमें संदेह है।

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

कर्नाटक और तेलंगाना के चुनावों के बाद भाजपा के खराब प्रदर्शन और कांग्रेस की बड़ी सफलता के लिए उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीतिक संस्कृति के अंतर को जिम्मेदार माना गया था। तब से यह तर्क दिया जाने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मुद्दे और भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति दक्षिण में नहीं चल सकती। इस आख्यान का इस्तेमाल लोगों को यह समझाने के लिए किया गया कि दक्षिण की 130 लोकसभा सीटों पर भाजपा आसानी से कब्जा नहीं कर सकती, चाहे प्रधानमंत्री मोदी कितना भी जोर लगा लें।

यह ऐतिहासिक रूप से सच है कि आपातकाल के बाद 1977 में जब इंदिरा गांधी का पतन हुआ था, तब कांग्रेस को दक्षिण भारत में ही शरण मिली थी। यहां तक कि 2014 और 2019 में जब कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई, तब भी दक्षिण भारत ने गांधी परिवार को मजबूत शरण दी थी। इससे भी पहले, जब 2004 और 2009 में कांग्रेस ने केंद्र में वापसी की कोशिश की, तो दक्षिण के मतदाताओं ने भरपूर समर्थन दिया था। लेकिन आज इस बात में संदेह है कि दक्षिण में वैसी ही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जमीनी वास्तविकता बदल रही है। दक्षिण में क्षेत्रीय दलों की भूमिका प्रमुख होती है।

निस्संदेह कर्नाटक एवं तेलंगाना की जीत ने कांग्रेस को बेहद जरूरी गतिशीलता प्रदान की है। फिर भी कांग्रेस दक्षिण को हल्के में नहीं ले सकती। अब उसे कई नई और चतुर क्षेत्रीय पार्टियों से जूझना होगा। भाजपा ने भी मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश नहीं छोड़ी है। भाजपा उत्तरी और पश्चिमी भारत में अपने चरम पर पहुंच चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री दक्षिण में दृढ़तापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले दो महीने में दक्षिण भारत की चार विस्तृत यात्राएं की हैं। चुनाव की घोषणा होने पर वह दक्षिण में और ज्यादा प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद कर्नाटक में अब भी भाजपा के लिए काफी संभावनाएं हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 28 में से 25 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस मात्र एक सीट जीत पाई थी। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव की अपनी जीत (135 सीटों और 42.88 फीसदी वोट) और भाजपा के विधानसभा प्रदर्शन (66 सीट एवं 36 फीसदी वोट) का लोकसभा में कैसे उपयोग कर पाती हैं। देवगौड़ा की पार्टी जनता दल (एस) के साथ गठबंधन करके भाजपा ने पारंपरिक रूप से त्रिकोणीय मुकाबले को सीधी लड़ाई में बदल दिया है और उसे वोक्कालिगा और लिंगायत वोटरों के एकसाथ आने की उम्मीद है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य पार्टी का नेतृत्व येदियुरप्पा खेमे को सौंपकर एक सुधार किया है। माना जाता है कि 'मोदी फैक्टर' लोकसभा चुनावों में भाजपा को बढ़त दिला सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्य के मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं।

तमिलनाडु में द्रमुक और कांग्रेस समेत उसके अन्य सहयोगियों के लिए एक परीक्षा होगी कि क्या वह पिछले लोकसभा चुनाव (39 में से 38 सीटें) और विधानसभा चुनाव (234 में से 159 सीटें) की तरह शानदार प्रदर्शन कर पाएगी। इस बार स्टालिन सरकार के खिलाफ भाई-भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के खिलाफ ड्रग तस्करों से मिलीभगत के कथित आरोप भी हैं। शीर्ष द्रमुक मंत्रियों के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि का बयान भी द्रमुक के पक्ष में काम नहीं कर सका। मुख्य विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक के. अन्नामलाई के नेतृत्व वाली भाजपा से पिछड़ गई है। अन्नामलाई के नेतृत्व में भाजपा को द्रमुक से लड़ाई करने के लिए नया जोश मिला है। अन्नाद्रमुक ने हाल ही में भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया है, जो अनुमानित रूप से 13 फीसदी अल्पसंख्यक मतों को द्रमुक से अलग करने के लिए था। इसके विपरीत मोदी ने काशी तमिल संगमम के जरिये भाजपा के हिंदुत्व और तमिल परंपरा के बीच एक भावनात्मक एवं सांस्कृतिक संबंध जोड़ने का प्रयास किया है।

तेलंगाना में कांग्रेस की रणनीतिक बढ़त और आत्मविश्वास से मोदी निश्चिंत हैं। भाजपा का दावा है कि तेलंगाना में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस बीआरएस से अलग नहीं है, जो अब भी हार के सदमे से उबर नहीं पाई है। भाजपा के लिए सकारात्मक बात यह है कि वह विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रही, जो कि उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वहां 17 में से चार सीटें जीती थीं। भाजपा-आरएसएस के आख्यान को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए तेलंगाना का सामाजिक चरित्र अनुकूल है। वहां मुस्लिम आबादी 15 फीसदी के करीब है, जो निजामाबाद जैसे जिलों में केंद्रित है, जहां भाजपा ने 2019 में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को हराया था। वहां मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी करती है।

आंध्र प्रदेश में भाजपा ने चंद्रबाबू नायडु की तेदेपा और पवन कल्याण की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहां मुख्य लड़ाई जगमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और तेदेपा के बीच है। कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटक और तेलंगाना की जीत का उसे फायदा मिलेगा। वाईएसआर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने वहां जगन मोहन की बहन वाईएस शर्मिला को पार्टी में शामिल किया है। ऐसी भी अटकलें हैं कि राज्य कांग्रेस अपने नए दुश्मन वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ तेदेपा से गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और भाजपा आठ से दस सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।

कांग्रेस को केरल से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली बार उसने 20 में से 15 सीटें जीती थीं। उसे उम्मीद है कि इस बार वह वामपंथियों को न्यूनतम स्तर पर ला देगी। 44 फीसदी मुस्लिम-ईसाई वोट बैंक कांग्रेस का पारंपरिक जनाधार है। इसी वजह से राज्य कांग्रेस की इकाई ने कांग्रेस कार्यसमिति के नेताओं को अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाने के लिए कहा था।

मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा ने भी हिंदू-ईसाई वोटों को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। भाजपा की नजर 18 फीसदी ईसाई वोटों पर है और वह अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर करने के लिए चर्च नेताओं से संबंध बढ़ा रही है। तो क्या उत्तर-दक्षिण का जो अंतर पैदा किया जा रहा है, वह भाजपा को रोक पाएगा?

जीवन धारा

गौर गोपाल दास

हमें अपनी प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। संतुलन का एक गहन आयाम, तथापि हमारे भीतर, आंतरिक स्तर पर रहता है, जो हमारे दृष्टिकोण और मूल्यों से बंधा होता है।

हम अपने जीवन की कहानियों के लेखक हैं

क्या आपको मानसून का अनुभव याद है? यह आसमान से पानी की सबसे भयंकर और गड़गड़ाहट भरी बौछारें लाता है। अगर आप इस भारी बारिश में फंस जाते हैं, तो सूखे रहना लगभग असंभव है। इसी तरह दुनिया की चुनौतियां और नकारात्मक परिस्थितियों में फंस जाना भी मुश्किल नहीं है। शांति की अनुभूति, प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस करना जीवन में चुनौतियों से बचना नहीं है, बल्कि इन चुनौतियों के बीच जीवन को इस प्रकार से निर्देशित करना है, ताकि हम अपनी पसंद का जीवन जी सकें।

यदि हमारे पास कोई सबसे मूल्यवान अधिकार है, तो वह है हमारी स्वतंत्र इच्छा, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हम अपने जीवन की कहानियों के लेखक हैं। हमारे ऊपर चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसे मानसून की बारिश हमारे सिर पर गिरती है। हम उन्हें खोजते नहीं, मांगते नहीं। वे स्वयं हमारे रास्ते में आती हैं। हमें यह तय करना होता है कि हमें उनसे कैसे निपटना है। खुशी अपने आपसे नहीं आती। बचपन से ही हमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों की विधिवत शिक्षा मिलती है, लेकिन आमतौर पर खुशी उन विषयों में सम्मिलित नहीं होती। निष्ठा और संतुलन के साथ जीना ही जीवन का अद्भुत रहस्य है। ये सरल सिद्धांत हैं, जिनका उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा संतुष्टि की भावना का अनुभव करने के लिए किया जा सकता है।

क्या आप कभी चिड़चिड़ाहट या निराशा महसूस करते हैं? क्या आपको कभी लगता है कि जीवन आपके इच्छित मार्ग पर नहीं चल रहा? अगर इनमें से किसी भी या सभी सवालों का जवाब हां है, तो यह एक संकेत है कि शायद आपका जीवन संतुलित नहीं है। जैसे चार पहियों पर कार संतुलित होती है, हमें अपने जीवन के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित करना होगा-हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे संबंध, हमारा कामकाजी जीवन और हमारा सामाजिक योगदान। बाहरी स्तर पर पहियों का संतुलन उनके सुनियोजन में निहित है। यह समय की आवश्यकता के अनुसार हमारी प्राथमिकताओं को समायोजित करने के विषय में है, जो सुनियोजन की स्थिति से बाहर है। जीवन में किसी विशेष समय पर, हमारे कामकाजी जीवन को हमारे व्यक्तिगत जीवन की तुलना में अधिक महत्व की आवश्यकता होती है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

संतुलन का एक गहन आयाम, तथापि हमारे भीतर, आंतरिक स्तर पर रहता है, जो हमारे दृष्टिकोण और मूल्यों से बंधा होता है। वह मानसिकता कार के पहियों में भरी गई हवा की तरह है। अगर कार के सभी पहियों में हवा का दबाव सही नहीं है, तो वह पंक्चर हो सकता है और हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचने से रोक सकता है। यही कारण है कि हमें संतुलन के आंतरिक पहलुओं का सही संचालन करना है।

जीवन का उद्देश्य...

सूत्र

कभी-कभी हमें खालीपन का अनुभव हो सकता है। हमें लग सकता है कि जीवन न जाने हमें कहां ले जा रहा है। इस समय हमें आध्यात्मिकता के स्टेयरिंग व्हील को मजबूती से, कसकर पकड़ना चाहिए। इस स्टेयरिंग व्हील के चार भाग होते हैं-हमारा आध्यात्मिक अभ्यास, संस्था, जिससे हम जुड़ते हैं, हमारा चरित्र और ईश्वर तथा दूसरों के लिए हमारा कार्य।

दूसरा पहलू

अक्सर गंभीर त्रुटियों से भरी किताबें प्रसिद्ध लोगों की मृत्यु के तुरंत बाद ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध रहती हैं।

एआई का चमत्कार मरते ही जीवनी तैयार

एलिजाबेथ ए हैरिस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिये जल्दबाजी में घटिया तरीके से उन लोगों की जीवनियां तैयार की गई हैं, जिनका अभी-अभी निधन हुआ है।

पिछले महीने *द न्यूयॉर्क टाइम्स* के पूर्व कार्यकारी संपादक जोसेफ लेलीवेल्ड के निधन के बाद उनके भाई माइकल लेलीवेल्ड यह देखने के लिए इंटरनेट खंगालने लगे कि उन्हें कैसे याद किया जा रहा है। लेलीवेल्ड की मृत्यु के तुरंत बाद के दिनों में उनके ऊपर अमेजन पर कम से कम आधा दर्जन जीवनियां प्रकाशित हुईं। उनमें से कई उसी दिन खरीद के लिए उपलब्ध थीं, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि उन किताबों में उनके भाई को एक चेन स्मोकर बताया गया है, जिन्होंने काहिरा में अपने पत्रकारिता कौशल को निखारा और वियतनाम से रिपोर्टिंग की। हालांकि इनमें से कुछ भी सच नहीं है। माइकल कहते हैं कि ऐसे लेखक आपके दुख के सौदागर हैं, जिनका उद्देश्य ऐसे दुखद क्षण में भी सिर्फ पैसे कमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिये जल्दबाजी में घटिया तरीके से उन लोगों की जीवनियां तैयार की गई हैं, जिनका अभी-अभी निधन हुआ है।

हाल ही में 1960 के दशक के प्रसिद्ध टेलीविजन शो *स्मदर्स ब्रदर कॉमेडी ऑवर* के टॉम स्मदर्स का एक अन्य मामला सामने आया। स्मदर्स की मृत्यु विगत 26 दिसंबर को हुई थी, और ठीक उसी दिन एक भद्दी और व्याकरण के लिहाज से गलत शीर्षक वाली नई किताब अमेजन पर उपलब्ध हुई।

अक्सर कोई भी प्रकाशन कंपनी सूचीबद्ध नहीं होती है और जिन लेखकों का नाम पुस्तक पर प्रकाशित होता है, वे काल्पनिक होते हैं या मृत भी।

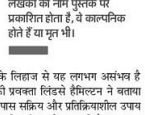

अमेजन ने इन पुस्तकों की बिक्री के बारे में सवालों के जवाब देने से इन्कार कर दिया, पर उनका प्रकाशन एक मजबूत व्यवसाय नहीं लगता है। उनमें से कुछ के पास ग्राहकों की कोई समीक्षा नहीं थी और जिनकी समीक्षा थी भी, उनमें किताब को बहुत खराब बताया गया था। जीपीटी जीरो के संस्थापक एडवर्ड तियान ने कहा, 'संख्या के लिहाज से यह लगभग असंभव है कि इन्हें किसी मनुष्य ने लिखा हो। अमेजन की प्रवक्ता लिंडसे हैमिल्टन ने बताया कि, 'सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास सक्रिय और प्रतिक्रियाशील उपाय हैं और हमने दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली कई पुस्तकें हटा दी हैं।' अक्सर कोई भी प्रकाशन कंपनी सूचीबद्ध नहीं होती है और जिन लेखकों का नाम पुस्तक पर प्रकाशित होता है, वे काल्पनिक प्रतीत होते हैं या यहां तक कि मृत भी। लोरी एम. ग्रेफ को कई अन्य लोगों के अलावा टोबी कीथ और जोसेफ लेलीवेल्ड पर लिखित पुस्तकों का लेखक बताया गया था। पर गूगल खोज में सबसे ऊपर 'लोरी एम. ग्रेफ' नाम की एक महिला पर श्रद्धांजलि आलेख है, जिसकी 2016 में मृत्यु हो गई थी।

©The New York Times 2024

आंकड़े

कम इंटरनेट सुविधा

कुछ राज्यों के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा का भारी अभाव है। इसमें सबसे कम सुविधा बिहार के स्कूलों में है।

राज्य	प्रतिशत
बिहार	5.8%
मिजोरम	5.9%
ओडिशा	8.1%
उत्तर प्रदेश	8.8%
तेलंगाना	9.23%

आंकड़े सबसे कम इंटरनेट सुविधाओं वाले राज्यों के हैं।
स्रोत : UDISE, 2021-22

जो यह कहता है कि मैं ज्ञानी हूं और बहुत कुछ जानता हूं, उसे यह समझ लेना चाहिए कि वह घोर अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है।

ज्ञान का अहंकार

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

एक युवा साधक ब्रह्मनिष्ठ संत पथिक जी महाराज के सत्संग के लिए पहुंचा। बातचीत के दौरान वह बार-बार कहता था, 'मैं बहुत धनी परिवार से हूं। मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और *गीता, महाभारत,* पुराणों आदि का अध्ययन किया है।'

संत ने कहा, 'यदि वास्तव में जिज्ञासा लेकर आए हो और धर्म-अध्यात्म का मर्म समझने की तृष्णा है, तो सबसे पहले इस अहंकार का त्याग करो कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो। अहंकार के रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। जो यह कहता है कि मैं ज्ञानी हूं और बहुत कुछ जानता हूं, उसे समझ लेना चाहिए कि वह घोर अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। न जानने का बोध ज्ञान की गुरुता का सर्वोपरि सम्मान है। वह परमात्मा के प्रति समर्पण भी है।'

उन्होंने आगे कहा, 'ज्ञान का अहंकार कुछ सीखने नहीं देता। जो मानव विनम्रतापूर्वक खुद को अज्ञानी मानकर ज्ञान प्राप्त तत्वदर्शी की शरण लेता है, वही आत्मा-परमात्मा व ज्ञान-अज्ञान के भेद को जान सकता है। जिसकी बुद्धि स्थिर है और जिसका मन कहीं अटका नहीं है, ऐसा विनयी जिज्ञासु ही ज्ञान के सागर में गोते लगाकर मोती ढूंढ सकता है। सबसे पहले किसी भी प्रकार के अहंकार से शून्य हो जाना जरूरी है।'

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला पुराने पन्नों से — 25 जनवरी, 1957

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी दोनों सीटों पर लड़ेगी

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी शहर की दोनों सीटों पर लड़ेगी
उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने आगरा शहर से विधान सभा का दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। छत्ता कोतवाली-क्षेत्र के लिए श्री किशनदयाल ऐडवोकेट व लोहामंडी-रकाबगंज क्षेत्र के लिए श्री रामचंद्र पालीवाल उम्मीदवार घोषित किये गये

उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने आगरा शहर से विधानसभा की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। उसने छत्ता कोतवाली और रकाबगंज, दोनों क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।

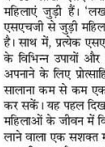

महिलाएं बन रहीं ग्रामीण विकास का इंजन

एसएचजी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का उपयुक्त माध्यम हैं, इसलिए इन्हें मजबूत किया जाना चाहिए।

मौसमी कबिराज
एसएचजी

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में महिलाओं का सामूहिकीकरण ग्रामीण भारत में विकास का इंजन रहा है। वर्तमान में 83 लाख एसएचजी से नौ करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। 'लखपति दीदी' पहल के तहत एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ में, प्रत्येक एसएचजी परिवार को मूल्यवर्धन के विभिन्न उपायों और आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे सालाना कम से कम एक लाख रुपये की आय प्राप्त कर सकें। यह पहल दिखाती है कि एसएचजी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और बदलाव लाने वाला एक सशक्त माध्यम है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण महिलाएं एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं। लेकिन 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की ग्रामीण कामकाजी आबादी में महिलाओं की संख्या 36.6 प्रतिशत, जबकि पुरुष की संख्या 78.2 प्रतिशत है। यहां महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में एसएचजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे समुदाय और बड़े हितधारकों के बीच एक पुल का काम करते हैं। लेकिन, एसएचजी के भीतर सूक्ष्म-उद्यमों को अपने व्यवसाय को टिकाऊ बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें तकनीकी जानकारियों का अभाव, पारंपरिक तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता, बाजार से अपर्याप्त संपर्क, सीमित कौशल प्रशिक्षण के साथ आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल की कमी जैसे कई कारण जिम्मेदार दिखाई देते हैं। चूंकि एसएचजी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचने और महिला नेतृत्व वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का उपयुक्त माध्यम हैं, इसलिए इन्हें मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं।

पहला कदम, सूक्ष्म उद्यम गतिविधियों से जुड़े एसएचजी को दीर्घकालिक बनाने के लिए उन्हें शुरू से अंत तक सहायता देना। इसमें क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधनों तक पहुंच की सुविधा और बाजार संपर्क की सहायता शामिल है। इससे एसएचजी को चुनौतियों से निपटने, अवसरों का लाभ उठाने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है, जो उनकी महिला सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करता है।

दूसरा कदम, महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए तैयार करना। सफल महिलाओं के लिए ऐसे अवसर बनाने चाहिए, जहां वे अपनी सफलता की कहानियों को अन्य महिलाओं के साथ साझा कर सकें और उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकें। उदाहरण के लिए, राजस्थान के दूनी गांव की मीरा जाट डेयरी और कृषि उत्पादक कंपनी मैत्री महिला मंडल समिति की प्रमुख हैं। यह समिति राजस्थान में 8,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देती है। आज जब वे चुनौतियों और अपनी सफलता की कहानी अन्य महिलाओं को सुनाती हैं, तब वे अधिक से अधिक महिलाओं को कामकाजी समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसा ही काम लखपति दीदियां भी कर सकती हैं, जिन्होंने एसएचजी के माध्यम से सफलता पाई है। वे सतत आय के विभिन्न उपायों को सामने लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

तीसरा कदम, उत्पादकता और आय को बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। उदाहरण के लिए, सोलर सिल्क रीलिंग मशीन, सोलर ड्रॉयर, बायोमास-संचालित कोल्ड स्टोरेज जैसी कई स्वच्छ प्रौद्योगिकियां कठिन परिश्रम को घटाने और मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने में मदद करती हैं। सीईईडब्ल्यू और विलग्रो का अध्ययन बताता है कि स्वच्छ प्रौद्योगिकियों ने ग्रामीण भारत की 10 हजार से अधिक महिलाओं की सालाना आय को 33 प्रतिशत बढ़ाने में मदद करते हुए उनकी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार किया है। राजस्थान में झाडोल गांव की आशापुरा एसएचजी की गायत्री सुथार के अनुभव को बतौर उदाहरण देखा जा सकता है। बिजली आपूर्ति में दिक्कत होने पर उन्हें डेयरी व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ता था। इससे बचने के लिए उन्होंने सोलर रेफ्रिजरेटर लगा लिया। अब वे सोलर रेफ्रिजरेटर को अपने कारोबार का रक्षक बताती हैं, क्योंकि इससे दूध की बर्बादी घटी है और आय बढ़ी है।

-साथ में अंगारिका गोगोई

edit@amarujala.com

दैनिक जागरण

संस्कृति समाज का प्रतिबिंब होती है

एक उपयोगी योजना

यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार धान की जगह दालें, मक्का और कपास उगाने वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उनकी पूरी उपज खरीदने की योजना लागू करने जा रही है। यह वही योजना है, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के किसान संगठनों को तब दिया था, जब वे अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे। उस समय पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर अन्य कृषक नेताओं और कृषि विशेषज्ञों से विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन फिर यकायक उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ऐसा करके उन्होंने एक अवसर गंवाने का ही काम किया। यह उचित ही है कि पंजाब के किसान संगठनों की बेरुखी के बावजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट किया कि इस योजना को अगले सीजन से देश भर में लागू किया जाएगा। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि एक तो पंजाब के किसान संगठन देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और दूसरे, यदि कोई उपयोगी योजना किसी राज्य विशेष के किसानों को रास नहीं आ रही तो इसका यह अर्थ नहीं कि उससे शेष देश के किसानों को भी वंचित रखा जाए। बेहतर होता कि पंजाब के किसान संगठन इस योजना पर सकारात्मक रवैये का परिचय देते।

पंजाब देश के उन राज्यों में शीर्ष पर है, जहां जरूरत से ज्यादा धान पैदा किया जा रहा है। धान उगाने में पानी की कहीं अधिक खपत होती है। पंजाब के किसान इससे भली तरह अवगत हैं कि भूजल के अत्यधिक दोहन से उसका स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन वे पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने को तैयार नहीं। यह रवैया तब है, जब पंजाब के कुछ इलाकों में भूजल स्तर कहीं अधिक नीचे चले जाने से खेती की जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे की अनदेखी का कोई औचित्य नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही किया जा रहा है। देश के किसी भी हिस्से के किसान हों, यह ठीक नहीं कि वे उन फसलों को उगाने की जिद पकड़े रहें, जिनकी मांग कम है और जिनमें पानी की भी कहीं अधिक खपत होती है। मक्का और कपास के साथ मसूर, उड़द एवं अरहर की खेती में केवल कम पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि उनकी मांग भी अधिक है। यह एक तथ्य है कि देश को दालों का आयात करना पड़ता है, जिसमें अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। दलहन जैसी स्थिति तिलहन की भी है। निःसंदेह एक समय था, जब गेंहू, धान की खेती को प्राथमिकता देना आवश्यक था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और समझदारी बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने में ही है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपनी योजनाओं के जरिये किसानों को वही फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिनकी मांग अधिक है और जो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं।

हवाई सेवा

उत्तराखंड में हवाई सेवाओं का निरंतर हो रहा विस्तार निश्चित रूप से अन्य राज्यों से इस प्रदेश के आवागमन को सुगम बना रहा है। इससे न केवल प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, बल्कि यहां की आर्थिकी को भी गति मिलेगी। उत्तराखंड तेजी से पर्यटन मानचित्र पर अपना स्थान बना रहा है। साथ ही यह निवेशकों के लिए भी एक उपयुक्त धरातल तैयार कर रहा है। अभी तक उत्तराखंड आने-जाने के लिए सड़क मार्ग का ही सबसे अधिक उपयोग होता है। इस कारण यहां तक पहुंचने का सफर थोड़ा लंबा है। हवाई सेवाओं के विस्तार से उत्तराखंड से देश के विभिन्न शहरों के बीच दूरी घटेगी और यात्रियों को भी सहूलियत होगी। हाल ही में प्रदेश सरकार ने देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए हवाई सेवा शुरू की है। अयोध्या के लिए शुरू की गई हवाई सेवा अयोध्या में बन रहे रामलला के दिव्य व भव्य मंदिर और बाल विग्रह के दर्शन करने की इच्छा रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसी प्रकार उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग अमृतसर एवं बाघा बार्डर तक जाते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी पंजाब से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। उनके लिए यह हवाई सेवा सुविधाजनक रहेगी। वाराणसी के लिए भी हवाई सेवा का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सरकार की योजना अब आने वाले समय में जम्मू समेत देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सेवाएं राज्य हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत शुरू की गई हैं। इसमें हवाई कंपनियों को सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। इस कारण यात्रियों को सस्ती दर पर टिकट मिल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल्द ही देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी इस योजना का संचालन आरंभ करेगी।

राज्य के स्तर से हवाई सेवा की शुरुआत यहां के पर्यटन और आर्थिकी को गति प्रदान करेगी

जनादेश का निर्धारण करतीं महिलाएं

राहुल वर्मा

केवल संख्या ही नहीं, राजनीतिक सक्रियता और मतदान का रुझान भी राजनीति में महिलाओं को महत्वपूर्ण बनाता जा रहा है

शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जानी-मानी लेखिका एवं समाजसेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुधा मूर्ति के मनोनयन को 'नारी शक्ति और देश की नियति को आकार देने में आधी-आबादी की भूमिका से जोड़कर' बधाई संदेश लिखा। महिला दिवस पर यह मनोनयन और प्रधानमंत्री का संदेश भले ही एक सांकेतिक कदम हो, लेकिन इसके बड़े गहरे मायने हैं। यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता एवं शक्ति को मिल रही मान्यता का प्रमाण है। यह अकारण भी नहीं है। वह समय बहुत दूर नहीं जब देश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों को पीछे छोड़ देगी। 2009 में कुल मतदाताओं में महिलाएं लगभग 46 प्रतिशत थीं। यह आंकड़ा 2019 में बढ़कर 48 प्रतिशत से कुछ अधिक हो गया। केवल संख्या ही नहीं, बल्कि सक्रियता और मतदान का रुझान भी महिलाओं को महत्वपूर्ण बनाता जा रहा है। पिछली सदी के छठे से आठवें दशक के बीच पुरुषों का मतदान महिलाओं से लगभग 12 प्रतिशत अधिक रहता था। आठवें दशक से पिछली सदी के अंतिम दशक तक यह अंतर आठ प्रतिशत रह गया। 2014 के चुनाव में तो पुरुष मतदान महिलाओं की तुलना में मात्र एक प्रतिशत अधिक रहा, जबकि 2019 के चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मतदान ने मामूली ही सही, लेकिन बढ़ोतरी दर्ज की। मतदान और राजनीतिक रुझान को लेकर महिलाओं की बदलती मनोवृत्ति के पीछे शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, जागरूकता और चुनाव आयोग के अभियान प्रमुख कारक हैं।

महिलाओं के बढ़ते मतदान की स्थिति में यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि राजनीति में उनकी पसंद कैसे निर्धारित होती है? इसकी कसौटियां देखी जाएं तो सबसे पहले कल्याणकारी योजनाओं का पैमाना आता है। दस वर्षों से केंद्र की सत्ता और कई राज्यों में सरकार चला रही भाजपा की चुनावी सफलता के पीछे महिला मतदाताओं की अहम भूमिका मानी जाती है। भाजपा ने शौचालय निर्माण से लेकर उज्ज्वला योजना और आवास में महिलाओं के स्वामित्व को प्राथमिकता देने जैसी उन योजनाओं पर दांव चला, जो सीधे महिलाओं और समग्रता में समूचे परिवार को लाभान्वित करने वाली हैं। कई राज्यों में भाजपा सरकारों ने महिलाओं को नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना भी शुरू किया है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना भाजपा के लिए बाजी पलटने वाली सिद्ध हुई। अब अन्य दल भी इस प्रकार की योजनाओं का आश्रय ले रहे हैं। महिला मतदाताओं को लुभाने में अन्य दल भी पीछे नहीं हैं। बिहार में शराबबंदी और साइकिल वितरण जैसी योजनाएं नीतीश कुमार के लिए महिला मतदाताओं को साधने में सहायक बनी हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में जयललिता ने महिला मतदाताओं को साधकर चुनाव की पूरी कहानी ही बदल दी थी। केरल में भी ऐसी ही कुछ परंपरा रही है। यहां तक कि बंगाल में भी ममता बनर्जी सरकार महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चला रही है।

शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक स्वावलंबन जैसे कारकों से बढ़ता महिलाओं का मतदान ● फाइल

केवल कल्याणकारी योजनाएं ही नहीं, कानून एवं व्यवस्था का मुद्दा भी महिला मतदाताओं की प्राथमिकता सूची में दिखता है। हाल के चुनावों में यदि भाजपा के पक्ष में महिला मतदाताओं का झुकाव बढ़ा है तो उसमें कानून एवं व्यवस्था जैसे पहलू की भी अहम भूमिका रही। भले ही भाजपा सरकारों में कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह चाकचौबंद न भी हो, लेकिन पार्टी का इस मुद्दे पर सख्त रवैया उसे लेकर एक सकारात्मक धारणा अवश्य बनाता है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें, जहां योगी आदित्यनाथ ने कानून एवं व्यवस्था को लेकर अपना एक माडल अपनाया है, जिसकी कुछ पैमानों पर आलोचना भले ही की जा सकती हो, लेकिन जनता में उसकी स्वीकार्यता दिखती है। खासतौर से कालेज जाने वाली लड़कियों या कामकाजी महिलाएं कानून एवं व्यवस्था को लेकर बहुत संजीदा होती हैं। यह उनके मतदान रुझान में भी दिखता है। 2022 में सीएसडीएस और एक्सिस के सर्वे के अनुसार सपा की तुलना में भाजपा को महिलाओं का समर्थन करीब 10 प्रतिशत अधिक रहा। भाजपा के रुख का लाभ उसके सहयोगी दलों को भी मिलता दिखाई देता है। बिहार में नीतीश कुमार ने जब राजद के साथ चुनाव लड़ा तो उन्हें महिलाओं का उतना समर्थन नहीं मिला, जितना उन्हें भाजपा के साथ चुनाव लड़कर मिलता रहा। प्रतीत होता है कि भाजपा महिला मतदाताओं की आकांक्षाओं और उनके मानस को अन्य दलों की तुलना में कहीं बेहतर पढ़ रही है। इसलिए प्रतीकात्मक कदम हो या कोई नीतिगत पहल, भाजपा आधी-आबादी का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करती है।

जब नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष बने थे, तब उन्होंने सांगठनिक पदों पर एक तिहाई महिलाओं को स्थान देने की बात कही थी। समय के साथ भाजपा में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है तो महिलाओं से जुड़ी इकाइयों को और समृद्ध बनाया गया है। संसद के नए भवन के उद्घाटन सत्र में पहला एजेंडा भी विधायी संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व देने से जुड़ी पहल का रहा। इससे महिलाओं को भले ही लोकसभा एवं विधानसभाओं में तत्काल उतना प्रतिनिधित्व न मिले, पर संदेश अवश्य गया कि भाजपा इस वादे को लेकर ठोस इरादा रखती है। महिला मतदाताओं को लामबंद करने के भाजपा के तरीकों में नवाचार दिखता है। स्वयं सहायता समूहों में बड़े पैमाने पर महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। उनसे प्राप्त डाटा का पार्टी अपनी लक्षित योजनाएं बनाने में उपयोग कर रही है। मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को सुगम ऋण मिल रहे हैं और उनमें उद्यमिता की आकांक्षाओं को परवान चढ़ाया जा रहा है। ड्रोन दीदी जैसी पहल से भी महिलाओं में पैठ बनाने का प्रयास है। यही कारण है कि पिछली सदी के अंतिम दशक में भाजपा को जहां महिलाओं के कम वोट प्राप्त होते थे, वहीं अब अधिक वोट मिल रहे हैं। दूसरे दलों को भी भाजपा की इस रणनीति की काट के लिए प्रभावी योजनाएं बनानी होंगी, क्योंकि आम चुनाव का जनादेश निर्धारित करने में महिलाओं की भूमिका अहम होगी।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो हैं)

response@jagran.com

भारत को फिर चिंतित करता नेपाल

डा. ऋषि गुप्ता

सदैव भारत विरोध की राजनीति करने वाले दल का नेपाल की सत्ता में साझीदार होना शुभ संकेत नहीं

नेपाल में तीसरी बार वाम गठबंधन वाली सरकार की वापसी हुई है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) और नेपाली कांग्रेस के बीच विवादों के कारण प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने गठबंधन से अलग होकर अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहे केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी एमाले) के साथ वापसी की। यह तीसरी बार है जब नेपाल के दो प्रमुख वाम दलों ने गठबंधन वाली सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री प्रचंड और केपी ओली के बीच हुए आठ सूत्रीय समझौते में अन्य दो दल भी साथ आए हैं, जिनमें जनता समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी शामिल है। नवंबर 2022 में हुए आम चुनावों के बाद यह तीसरी बार है, जब नेपाल में सरकार का नए सिरे से गठन हुआ है। यह नेपाल के राजनीतिक इतिहास में अवसरवाद का एक और उदाहरण है। नेपाल में 2008 में राजशाही के पतन के बाद से जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं, उनमें से किसी ने भी पांच वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। नेपाल ने 16 वर्षों में औसतन हर साल एक नया प्रधानमंत्री देखा है। शायद इसी कारण वहां की जनता ने नए दलों को मौका दिया है। दुर्भाग्य से नए दलों ने भी जनता को निराश ही किया है।

मौजूदा वाम गठबंधन में शक्ति संतुलन पर ध्यान दिया जाए तो यह अत्यधिक अस्थिर है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि माओवादी सेंटर के पास एमाले (78 सीटें) की तुलना में कम सीटें हैं, फिर भी उसके प्रमुख प्रचंड प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चूंकि अतीत में केपी शर्मा ओली ने प्रचंड को कम सीटों (32) के कारण प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, इसलिए यह मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ओली प्रधानमंत्री बनना चाहें। यह भी संभव है कि इसके लिए उनकी पार्टी सबसे अधिक सीटों (88) वाली नेपाली कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले। वाम दलों की मौकापरस्ती और उनके नेताओं के स्वार्थों के चलते नेपाली जनता का एक हिस्सा राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी की पुरजोर वकालत करता आया है। हाल में नेपाली कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय समिति में हिंदू राष्ट्र के दर्जे की बहाली पर लंबी बात हुई। नेपाल के राजनीतिक हलकों में इसे ही माओवादी सेंटर-नेपाली कांग्रेस गठबंधन टूटने का एक तात्कालिक कारण माना जा रहा है।

फिर साथ आए प्रचंड और केपी शर्मा ओली। एएनआइ

यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो यह साफ दिखेगा कि राजशाही ने अपने दो सौ वर्षों के इतिहास में नेपाल को जोड़े रखा और राष्ट्रहित में कई कार्य भी किए। नेपाल में आज भी अस्सी प्रतिशत आबादी हिंदू है। चूंकि वहां राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, इसलिए जनता की आस्था राजशाही से जुड़ी हुई है। हालांकि नेपाल की हिंदू राष्ट्र के रूप में वापसी मुश्किल होगी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात एक हिंदूवादी आंदोलन की ओर इशारा जरूर करते हैं। प्रचंड के नेतृत्व वाली नई सरकार नेपाल और भारत के संबंधों पर भी गहरा असर डाल सकती है, क्योंकि वाम दलों की पूरी राजनीति भारत विरोध पर केंद्रित रही है। 2008 में माओवादियों ने अपनी पहली सरकार के दौरान चीन को प्राथमिकता देते हुए एक नई विदेश नीति की स्थापना की थी, लेकिन प्रधानमंत्री प्रचंड को जल्दी ही यह समझ आ गया था कि नेपाल का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और रोटी-बेटी का संबंध आदि भारत से दूरी बनाने की इजाजत नहीं देते। नेपाल के लिए भारत से अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है, लेकिन एमाले ने सदैव भारत विरोध की ही राजनीति की है। नेपाल के वाम दलों ने चीन से सैद्धांतिक जुड़ाव के बहाने 2017 में यह जानते हुए भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआइ परियोजना पर सहमति जताई थी कि इसका असर भारत की सुरक्षा पर भी हो सकता है।

चीन लगातार नेपाल पर दबाव डालता रहा है कि वह भारत से दूरी बनाए और सुरक्षा मामलों में बीजिंग का साथ दे। चीन को नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों से लगातार भय बना रहता है और वह प्रयास करता है कि तिब्बत की आजादी की मांग कर रहे लामाओं को नेपाल बंदी बनाए या फिर उसके हवाले करे। वाम दल हमेशा से इस मुद्दे पर चीन के साथ सहमत रहे हैं, जिसका अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार विरोध किया है। चीन के कुटिल इरादों के कारण नेपाल का एक तबका बीआरआइ का विरोध करता रहा है। हाल में हुए अध्ययन दर्शाते हैं कि बीआरआइ के तहत चीन अपनी दमनकारी और विस्तारवादी नीतियां ही आगे बढ़ा रहा है। इससे नेपाली जनता सशंकित है। हालांकि नेपाल में अभी तक बीआरआइ के तहत कोई भी तय कार्य पूरा नहीं हो सका है, फिर भी चीन चाहता है कि बात आगे बढ़े और इसीलिए नेपाल में सत्ता परिवर्तन होते ही चीनी विदेश मंत्रालय ने नेपाल की नई सरकार का स्वागत किया और साथ काम करने की इच्छा जताई। यह तय है कि बीआरआइ परियोजना चीन की प्राथमिकता में रहेगी।

नए विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठा ने भारत और चीन के साथ 'सम-दूरी' की नीति का वादा किया है। यह नीति अव्यावहारिक है। नेपाल भारत और चीन के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वह चीन की तुलना में भारत पर अधिक निर्भर है। चूंकि नेपाल भू-आबद्ध देश है, इसलिए वह विश्व व्यापार भारत के रास्ते ही करता है। ऐसे में नेपाल को यह समझने की जरूरत है कि वह भले ही भारत के साथ इतिहास को बदल ले, लेकिन वह भूगोल और लोगों के आपसी संबंधों को नहीं बदल सकता। मालदीव के घटनाक्रम के बाद भारत को नेपाल में जो कुछ हो रहा है, उस पर नजर रखने की जरूरत है।

(लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सहायक निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रकृति का नियम

विकट परिस्थितियों का सामना करने की हमारी एक क्षमता होती है। ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति जल्द निराश होने लगते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर की मर्जी या नियति की गति मान लेते हैं। जो लोग ऐसी स्थितियों में अपना धैर्य खो देते हैं, सबसे अधिक संकट में वही फंसते हैं। अधीर होकर वे ईश्वर की सत्ता पर ही सवाल उठाने लगते हैं कि यह जीवन क्यों दिया और दिया तो उसमें दुख के इतने थपेड़े क्यों दिए। दुख दिए तो दुख का निवारण क्यों नहीं हो रहा है। जबकि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि इस प्रकृति ने हमें जन्म दिया, तो इस नाते हम सभी उसकी ही संतान हैं। कोई अपनी संतान से कैसे विमुख हो सकता है।

इस प्रकृति को सबका ध्यान है। उसको हम सभी का स्वभाव भलीभांति पता है। उसे सबकी क्षमता पता है। उसे यह भी पता है कि किसी को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए उसके जीवन में कितना संघर्ष आवश्यक है। अन्यथा व्यक्तिगत स्वभाव या प्रकृति के अनुसार अस्तित्व में बने रहने के लिए जरूरी क्षमताएं विकसित नहीं हो पाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे तितली। अगर तितली के लिए चुनौतीपूर्ण क्षण किसी भी प्रकार आसान हो जाए तो तात्कालिक तौर पर तो वह उसके लिए बेहतर है, लेकिन उसके बाद की चुनौती वह सह नहीं पाती। ओशो कहते हैं, 'अगर बहुत सुरक्षा मिले और कोई संघर्ष न हो, तो रीढ़ टूट जाती है। रीढ़ बनती ही संघर्ष में है। तुम जितना संघर्ष करते हो, उतनी ही रीढ़ मजबूत होती है।'

इसलिए हमें प्रकृति के नियम पर भरोसा रखना होगा। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। वह बस यही चाहते हैं कि हमारा जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं। याद रखिए कि जिसके जीवन में अभूतपूर्व संघर्ष आया है, वही अभूतपूर्व सफलता के योग्य बन सका है। वह उन करोड़ों लोगों से अलग है, जिसने उनकी तुलना में आसान जीवन जिया है।

लवली आनंद

बड़े धोखे हैं साइबर दुनिया की राह में

गीता यादव

आनलाइन डेटिंग और रोमांस एप के जरिये दुनियाभर में ठगी के मामले बढ़े हैं

इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर नए-नए लोग आपको मिलते हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं। कई बार यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। देखा जाए तो नए तरह के सामाजिक रिश्तों का यह मायावी संसार बेहद लुभावना है। इसके माध्यम से अनजाने रिश्ते आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन देखने में जो इंटरनेट मीडिया रोमांचक है, उसके खतरे भी हजार हैं। क्योंकि जब चैटिंग से शुरू हुई दोस्ती का सफर छेड़खानी, दुष्कर्म, यौन शोषण, शादी के नाम पर झांसे और आर्थिक शोषण से खत्म होता है, तब स्थिति बहुत दुखदाई हो जाती है। पुलिस आंकड़ों पर गौर करें तो, इंटरनेट मीडिया और डेटिंग साइट्स ने लड़कियों के अपहरण की घटनाओं का ग्राफ बढ़ा दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अपहरण के जो मुकदमे लिखे गए, उनमें बड़ी संख्या में आरोपित से पहचान इंटरनेट मीडिया पर हुई थी। साथ में जीने-मरने की कसमें खाई गईं। लड़कियों ने घर छोड़ा। जब अहसास हुआ कि भूल हो गई तब तक देर हो चुकी थी। इंटरनेट मीडिया के जरिये दोस्ती करके शादी करने का झांसा देने और दुष्कर्म करने जैसे मामले भी बढ़ रहे हैं। वर्चुअल चैट्स और वीडियो कालिंग के जरिये मुलाकातों ने अपराधियों के लिए नए-नए रास्ते खोल दिए हैं।

फेसबुक पर कम से कम 20 प्रतिशत ऐसे यूजर्स हैं, जो फर्जी नाम, पहचान और फोटो का इस्तेमाल करके चैटिंग करते हैं। बेहतरीन प्रोफाइल बनाकर पहले दोस्ती और फिर बातें। फिर यह कहना कि भारी मुसीबत में फंस गया हूं और फिर शुरू हो जाता है ठगी का धंधा। इंटरनेट मीडिया पर फोटो के साथ-साथ वीडियो अपलोड करने का शौक भी लोगों में बढ़ा है। लेकिन अब यह भी बेहद खतरनाक बनता जा रहा है, क्योंकि एआइ के माध्यम से आवाज चुराई जा रही हैं। बाद में उसका इस्तेमाल आपको ठगने के लिए किया जा सकता है।

इस विषय से जुड़े शोधकर्ताओं ने पाया है कि आनलाइन रोमांस से जुड़ी धोखाधड़ी की रणनीति सोच-समझकर बनाई जाती है। जिसके कई चरण होते हैं, आकर्षक प्रोफाइल बनाकर पीड़ितों को फंसाना, पीड़ितों से आत्मीय बातचीत करना, पैसे ऐंठने के लिए संकट की स्थिति पैदा करना उसके बाद पीड़ितों को ब्लैकमेल कर ठगना। अनुसंधान से पता चला कि ठग पीड़ितों से पैसा ठगने के लिए विभिन्न सोशल इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने पिछले साल दुनिया के 194 देशों को अलर्ट जारी किया था। इसमें भारत भी शामिल है। अलर्ट के मुताबिक इंटरनेट मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। अपने प्रोफाइल में निजी जानकारियों को शामिल न करें। ठगी का शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्प लाइन नंबर और अपने नजदीकी साइबर थाने में लिखित शिकायत दें।

(लेखिका पत्रकार हैं)

समान नागरिक संहिता का समय

'समान संहिता के केंद्र में आएं महिलाएं' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में नाइश हसन ने यथार्थ ही लिखा है कि समान नागरिक संहिता के मसौदे पर बहस करते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी समुदायों की महिलाओं की भागीदारी और लैंगिक समानता का नजरिया उसके केंद्र में हो। संविधान के अनुच्छेद-44 का भी यही आशय है। हमारे समाज में शादी, उत्तराधिकार, तलाक और बच्चों के संरक्षण जैसे मुद्दे बहुत भावनात्मक हैं। मुद्दा यही है कि सभ्य समाज और राष्ट्र में किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय किसी प्रकार की रीति-रिवाजों के नाम पर न होकर संवैधानिक एवं मानवीय आधार पर होना चाहिए। इसीलिए समय की मांग है-समान नागरिक संहिता। देश में इसके न होने से कितनी पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में पहल की है, जिसका स्वागत होना चाहिए। उत्तराखंड की यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर आकार लेनी चाहिए। इस दिशा में जो भी अवरोध हों, उन्हें सार्थक प्रयासों से अविलंब दूर किया जाए।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

सीमा पार का आतंकवाद

'सीमा पार का आतंकवाद' शीर्षक से संपादकीय टिप्पणी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के सीमा पार इलाकों में जितने आतंकी हमले हुए और हो रहे हैं, उनका सूत्रधार पाकिस्तान है। हर बार वही होता आया है, जो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की वार्ता के दौरान हुआ है। इन आतंकी हमलों को लेकर जिस प्रकार से विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को आड़े हाथों लिया है, जाहिर है दोनों देशों के बीच संबंध और खराब होंगे। ऐसे में आमने-सामने बैठने का कोई तुक नहीं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का ''आका'' है। उनकी कपट नीति से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के नापाक इरादे को पलटवार से मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है।

कृष्ण खन्ना, दिल्ली

मेलबाक्स

ईवीएम पर सवाल का औचित्य

देश में लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा निर्वाचन आयोग कभी भी कर सकता है, लेकिन ईवीएम को लेकर नेताओं में अभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बेमतलब शंकाओं और आधारहीन आरोपों का निवारण इस बार चुनाव आयोग द्वारा सख्ती से प्रारंभ में ही किया जाना चाहिए। क्योंकि यह विषय देश की साख के साथ दुनिया के सबसे बड़े निष्पक्ष, स्वस्थ व मजबूत लोकतंत्र से भी जुड़ा एक विषय है। कुछ नेताओं की अनर्गल बयानबाजी और सतारूढ़ दल के राजनीतिक अंधविरोध के कारण जनमानस में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और तब चुनाव परिणाम निल बटा सन्नाटा नजर आता है। जैसे तमिलनाडु से एक कटु आवाज आती है कि भारत एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक उपमहाद्वीप है। राज्यसभा सीट जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एक नेता देश के प्रधानमंत्री के परिवार और हिंदू होने पर ही उंगली उठा देता है। बंगाल में संदेशखाली तृणमूल कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है और भविष्य में भिन्न परिणामों को ध्यान में रखकर ईवीएम पर ही कटाक्ष किया जाता है। कोई नेता उत्तर भारत को गौमूत्र राज्य कहता है। कोई नेता पवित्र ग्रंथ श्रीरामचरितमानस पर ही अमर्यादित टिप्पणियां कर देता है। कभी मतदाता के सोच को ही सतही बता दिया जाता है। कोई नेता देश के प्रधानमंत्री पर ही भड़ास निकाल चौथी फेल की संज्ञा दे देता है। तुष्टीकरण की आड़ में अयोध्या में नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक इवेंट से जोड़ना, मुहूर्त पर सवालिया निशान लगाना और सही जगह पर निर्माण नहीं करने से उसे जोड़कर जनता को बरगलाने की असफल कोशिशें की गईं। जिसके नकारात्मक प्रभाव से आमजन की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसका दुष्परिणाम लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिख सकता है। तब नेताओं द्वारा सारा ठीकरा ईवीएम की कार्यप्रणाली पर थोप दिया जाएगा।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

10 वर्ष जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान किया गया है, प्रश्नपत्र लीक मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को।

प्रश्नपत्र लीक प्रकरण

नए कानून के अनुरूप हो कठोर कार्रवाई

देश के अलग-अलग राज्यों में प्रश्नपत्र लीक का मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में यह घटना राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुकी है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया धांधली और अनियमितता के कारण आजकल चर्चा में है। नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण ले रहे कुछ ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को फर्जी तरीके से नौकरी पाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा सभी दोषियों के विरुद्ध नए कानून के अनुरूप कठोर कार्रवाई होनी चाहिए

कैलाश बिश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक मामलों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। प्रतीकात्मक

आज देशभर में प्रश्नपत्र का लीक होना एक विकट समस्या बन गई है। हाल के वर्षों में टेक्नोलाजी का जैसे-जैसे प्रचलन बढ़ा है, वैसे-वैसे देश के विभिन्न राज्यों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं प्रश्नपत्र लीक हुए बिना कराने की चुनौती भी बढ़ गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 15 राज्यों में प्रश्नपत्र लीक के मामले समाने आए और लगभग 41 नौकरी भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हो गया था। बीते कुछ वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने का सपना देखने वाले मेहनती छात्रों के लिए प्रश्नपत्र लीक एक ऐसा विश्वासघात बन गया है जो पूरे सिस्टम की शुचिता को कठघरे में खड़ा करता है। प्रश्नपत्र लीक एक ऐसी खाई है जिसमें हमारे सपने, उम्मीदें और उम्र सब डूब जाते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो देश विश्वगुरु बनने का दावा कर रहा हो, उस देश के सामने सरकारी नौकरी की परीक्षा कराना चुनौती क्यों बन गई है?

सरकारें नौकरियों को लेकर बड़े-बड़े इंतजाम करने का दावा करती हैं, पर वे वादे नकलमाफिया के आगे घुटने टेक देती हैं। प्रश्नपत्र लीक की बारंबार घटनाएं किसी भी राष्ट्र की शिक्षा और शिक्षा नीति की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं। प्रश्नपत्र लीक होने से शिक्षा क्षेत्र की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है, वहीं लोगों के मन में शिक्षा प्रणाली के प्रति भरोसे में कमी आती है। शिक्षा जगत का यह संकट मूलतः विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है। भर्तियों में घोटाला बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पूरे युवा समाज में कुंठा और अवसाद पैदा करता है और परीक्षाओं में गड़बड़ियों की बात सामने आने के बाद कई उम्मीदवार टूट जाते हैं।

काला कारोबार : मां-बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बनाते हैं। बच्चे सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। देश में हर साल लगभग डेढ़ करोड़ युवा नौकरी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। देश में नौकरी पाना कितना कठिन है, इसे इस बात से समझिए कि इसकी तैयारी करने वाले हर छात्र को औसतन सवा तीन साल तैयारी करनी पड़ती है। प्रतिवर्ष नौकरी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की संख्या का औसतन तीन करोड़ है। वस्तुतः सरकारी नौकरियों में सुरक्षा ज्यादा है, लेकिन संख्या बहुत ही कम है। इसलिए सरकारी नौकरी पाने और दिलाने के नाम पर होता है प्रश्नपत्र लीक। इसमें कमाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटी से छोटी नौकरी का पेपर लीक होने के बाद लगभग 20 लाख प्रति छात्र के हिसाब से बिक जाता है। यह काला धंधा हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है।

कई अभिभावक अपने जीवन की सारी जमापूंजी बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा देते हैं। सरकार भी इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए नियामक एजेंसियों के जरिये मोटी रकम निवेश करती है, फिर भी इस पर रोक नहीं लग पा रही। अक्सर तमाम इंतजामों के बावजूद आखिर किसी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक हो जाते हैं। साथ ही इस तरह की घटना पहली या नई नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने सुनने में आती रही हैं।

संगठित तंत्र : जिस निरंतरता से और जितने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में गड़बड़ियां देखी जा रही हैं, उससे यह संदेह होना स्वाभाविक है कि इसके पीछे कुछ संगठित गिरोहों का हाथ है, जिनकी सिस्टम के अंदर घुसपैठ है। ऐसे में इसे रोकने के लिए निश्चित रूप से बड़े प्रयासों की जरूरत है। सरकारी एजेंसियों की जांच के दौरान यह बात भी आई है कि संगठित गिरोह के तार कोचिंग सेंटरों से होकर परीक्षा कराने वाली एजेंसियों और सरकारी विभागों के लोगों से भी जुड़े हैं। कई बार कोचिंग सेंटर संचालक, परीक्षा कराने वाली एजेंसी और सरकारी विभाग के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रश्नपत्र लीक करवाने वाले नेटवर्क संगठित होकर इसे अंजाम देते हैं। दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर और पटना जैसे बड़े स्टडी सेंटरों पर, जहां लाखों की संख्या में लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, वहां प्रश्नपत्रों के लीक करवाने वाले नेटवर्क को चलाने वाले बरसों से इस काम में लगे हैं। पेपर लीक नेटवर्क इस हद तक संगठित है कि ऊपर (एग्जाम कराने वाली एजेंसी) से लेकर नीचे (पुलिस और सरकारी वकील) तक सब कुछ पहले से सेट कर लिया जाता है। प्रश्नपत्र लीक करवाने के इस धंधे के एक बड़े खिलाड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। छात्रों के जरिये पैसा उगाही और उसे आगे तक पहुंचाना कोचिंग सेंटरों के जिम्मे होता है। इससे कोचिंग का लाभ बढ़ जाता है। उसके छात्रों का चयन होने से उसकी साख भी बढ़ती है, जिससे उसे आगामी परीक्षाओं में और अधिक रकम वसूली का कारण मिल जाता है।

जब भी पेपर लीक होते हैं, दूसरे के नाम पर परीक्षा देते लोग पकड़े जाते हैं, आंसर शीट में बेईमानी पकड़ी जाती है, तब एग्जाम माफिया के नाम पर कुछ धरपकड़ होती है, बहुत से बहुत कुछ बाबू धरे जाते हैं। लेकिन परीक्षा बोर्ड के आला अधिकारियों पर कोई आंच नहीं आती। परीक्षा सही से कराने का चक्रव्यूह रचने वाले को छुआ तक नहीं जाता, जबकि पैदल सेना के सिपाही पकड़े जाते हैं। यह एक अजीब सिस्टम है। यह पहले ही क्यों मान लिया जाता है कि परीक्षा-भर्ती बोर्डों के अफसर बेदाग हैं, एग्जाम माफिया के करोड़ों के खेल में उनका कोई हाथ नहीं है? जबकि यही आला अफसर परीक्षा के पहले अपने चक्रव्यूह में बायोमेट्रिक व्यवस्था, फेशियल रिकग्निशन, मोबाइल जैमर, सीसीटीवी, स्कैनिंग, एक्सरे और न जाने क्या-क्या इंतजामों का बखान करते नहीं थकते हैं। लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने पर उन्हें कठघरे में खड़ा नहीं किया जाता।

परीक्षा में गड़बड़ी रोकने का कानून

पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, खासकर लोक सेवा आयोगों में भर्ती के लिए। परीक्षाओं में धोखाधड़ी और बेईमानी के कारण वर्ष 2023 में उत्तराखंड ने सख्त कानून बनाया। गुजरात में आलम यह रहा कि वर्ष 2015 के बाद से राज्य बिना प्रश्नपत्र लीक के एक भी भर्ती परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं हुआ है। इसीलिए फरवरी 2023 में गुजरात विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी को दंडित करने के लिए एक कानून भी पारित किया। अन्य राज्यों जैसे राजस्थान (2022), उत्तर प्रदेश (1998 में पारित अधिनियम) और आंध्र प्रदेश (1997 में पारित अधिनियम) में भी समान कानून हैं। लेकिन सख्त कानून के अभाव में प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं थम नहीं रही थीं। ऐसे में अधिकतर राज्य चाहते थे कि केंद्र सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए, ताकि सभी राज्य उसके दायरे में आएंगे और प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं को अंजाम देने वाले माफियाओं पर अंकुश लगे। राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों केंद्र सरकार भी एक सख्त कानून लेकर आई है। इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, डमी कैंडिडेट्स और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए कई कड़े प्रविधान शामिल किए गए हैं। प्रश्नपत्र लीक मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपये जुर्माने का प्रविधान किया गया है। वहीं डमी कैंडिडेट्स यानी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में तीन से पांच साल की सजा का प्रविधान किया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई संस्थान प्रश्नपत्र लीक मामले में शामिल पाया जाता है तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूल किया जाएगा। साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

अगर राज्य सरकारें ईमानदारी से नकल माफिया के खिलाफ नकेल कसना चाहें तो उनके पास मजबूत कानूनी आधार है, जिसके जरिए वे इन पर नकेल कस सकती हैं। हालांकि शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने आगे बढ़कर इस मामले में पहल की तथा विधेयक पेश करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के पास परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने या नकल करने जैसे अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है, इसलिए जरूरी है कि परीक्षा की प्रणाली की कमजोरी का लाभ उठाने वालों की पहचान की जाए और उनसे कठोरता से निपटा जाए। (कैलाश बिश्नोई)

आगे की राह : सरकारी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया में मेरिट, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता मूल मानक माने जाते हैं। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यही है कि गरिमा हर स्तर पर कायम रखी जाए। देशभर में विभिन्न भर्ती आयोगों और संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बनाई गई ओएमआर को अभ्यर्थियों द्वारा खाली छोड़ने और बाद में परीक्षा एजेंसियों मैं बैठे लोगों के माध्यम से साठगांठ करके उसे भरने की घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी चाहकर भी ओएमआर आंसरशीट में परीक्षा के दौरान या बाद में कोई गड़बड़ी न कर सके। तभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह से प्रामाणिक, पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित और निष्पक्ष हो सकेंगी। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं का परीक्षा आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे परीक्षार्थियों के मन में परीक्षा संस्था के प्रति विश्वास बना रहे, इसके लिए भी निरंतर प्रयासरत रहना आवश्यक है। नकल रोकने के लिए पुलिस एवं गुप्तचर एजेंसियों में बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है। भर्ती परीक्षाओं के समूचे सिस्टम को ऐसा बनाने की जरूरत है, ताकि उसमें सेंध नहीं लगाई जा सके। आमतौर पर देखा गया है कि प्रश्नपत्र लीक की अधिकांश घटनाएं भर्ती एजेंसियों के कर्मचारी और प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े लोगों की मिलीभगत से होती हैं। इन लोगों पर नए कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई होगी तो संगठित गिरोह नहीं पनप सकेंगे।

खरी-खरी

एक गधे की वापसी!

पूरन सरमा

गधा चला गया था, मैंने राहत की सांस ली। चलो मूर्ख गया। लेकिन वह फिर वापस आ गया। मैंने अपने तमाम परिचितों को बताया भी कि गया हुआ गधा वापस आ गया है। वे बहुत खुश हुए कि अब उन्हें चांस आसानी से मिल जाएगा। वे नहीं चाहते कि कोई समझदार आकर उनके अधकचरेपन को नकारे। इसलिए उन्होंने खुशियों के दीप जलाए। भरोसी लाल तो उलटा मुझे चिढ़ाने आए कि अच्छा हुआ वह आ गया। लो, वह तो लौट आया है। मैंने उनसे कहा, 'भाई इसका वापस लौटना शुभ नहीं है।' भरोसी लाल बोले, 'फिर हम क्या करेंगे? हमें तो ऐसा ही चाहिए।'

'भाई, साहित्य में गधों की आवश्यकता किसी काल में होने का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। ऐसा करो, इसे सिर पर बैठा लो।' मैंने कहा तो भरोसी लाल बोले, 'हमारा गधा, हम कुछ भी करें। अब साहित्य की दुनिया में हम होंगे और हमारा गधा। पता है गधे की महत्ता। बोझ ढोता है ओर अत्यंत निरीह होता है। इसलिए हम उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे।' मुझे लगा मेरे चारों ओर गधे इकट्ठे हो गए हैं और वे सब एक साथ रेंक रहे हैं। भरोसी लाल बोले, 'उन्हीं के बल पर आज मैं संपादक बना हूं। श्याम सुंदर जी को सेमिनार का ठेका दिया गया है, वरना पहले वाला तो घाघ था। हमें घास ही नहीं डालता था।'

'यार भरोसी लाल, तुम्हारी घास के लिए संस्था का नाश क्यों करा रहे हो। मुझसे किसी तरह के सहयोग की आशा मत करना। कल गधे ने दुलत्ती मार दी तो रूआंसे होकर मेरे पास रोना मत रोना।' मैंने कहा तो वे बोले, 'अरे आप से सहयोग करने को कहा किसने है? अब तो हमारी अपनी पूरी जमात है। आप जैसा सुजान चाहिए भी नहीं। उसे अपना समय निकालना है और हमें अपने उल्लू सीधे करने हैं। इसलिए गधे की वापसी का हम स्वागत करते हैं। हमारे मधुबन में वह लीद भी करेगा तो हम उसे फेकेंगे नहीं। हमारे साथ 'एक ढूंढो हजार मिलते हैं', वाली भीड़ है।'

मैं उदास हूं गधे की वापसी से, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता। ऊपर से थोपा हुआ है। गधे के समर्थक तालियां इतनी जोरों से बजा रहे हैं कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा।

पोस्ट

द्रमुक नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा जैसे लोगों को बोलने दिया जाना चाहिए। कम से कम यह पता चलता रहता है कि कैसी-कैसी विषैली विचारधाराएं इस देश में पाल-पोस कर रखी गई हैं।
दिव्य कुमार सोती @DivyaSoti

मोदी जी को मालूम है कि युवा लोगों को कैसे लुभाना है, वे कैसी भाषा में बात करते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के अवार्ड समारोह में उन्होंने जो कनेक्ट बनाया, वह बताता है कि वह हर वर्ग से अपना जुड़ाव बनाने में माहिर हैं। जगदीश भाटिया @jagdish

पद्मभूषण श्रीमती सुधा मूर्ति का राज्यसभा में मनोनयन स्वागतयोग्य है। उनका शिक्षा और समाजसेवा में अनुकरणीय योगदान है। उनकी सादगी और सरलता प्रभावित करती है। उच्च सदन उन जैसी हस्तियों के लिए ही है।
रवींद्र वाजपेयी @ravindrabajpai5

इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जितनी भी तारीफ की जाए, उतनी कम है। उन्होंने एजेंडाजीवी प्रदर्शनकारियों को हरियाणा की सीमा पर ही रोक दिया। इससे पूरे विरोध-प्रदर्शन की हवा निकल गई। अन्यथा लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान अराजक तत्व ही सुर्खियों में छाए रहते। अभिषेक @AbhishBanerj

जागरण जनमत कल का परिणाम

एसबीआइ को चुनावी बांड संबंधी सूचना साझा करने हेतु और समय मिलना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या राहुल गांधी को वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

भाता जिनको है नहीं चहक रहा कश्मीर,
उनके ही सिर हो रही बड़ी आजकल पीर।
बड़ी आजकल पीर फहरता वहां तिरंगा,
करते थे हर रोज जहां आतंकी दंगा।
रहे मचाते लूट वहां बन भाग्य विधाता,
बदल रहा कश्मीर भला क्यों उनको भाता!
- ओमप्रकाश तिवारी

विकाश चन्द्र पाण्डेय
vikash@pat.jagran.com

बिहार डायरी

भाजपा की असली आकांक्षा बिहार विजय

अभी चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हुई भी नहीं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच दिन के भीतर बिहार में तीन बड़ी जनसभाएं कर गए। दो मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय के बाद छह मार्च को बेतिया में। उन तीनों जनसभाओं में जुटी भीड़ अगर वास्तव में अपना वोट है तो फिर भाजपा की आकांक्षा सुखद परिणाम में परिवर्तित हो सकती है। हालांकि जुटान तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी जबरदस्त हुई थी, लेकिन उसके बाद घर भीतर ही अलगाव की कहानी शुरू हो गई। राजद के पांच और कांग्रेस के दो विधायकों को तोड़ भाजपा ने विधानसभा में अपने लिए रोहतास और कैमूर जिला का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया, जहां से उसका कोई विधायक नहीं था। ऐसा तब जबकि विधानसभा चुनाव से डेढ़ वर्ष पहले हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं क्षेत्रों में उसकी विजय दुंदुभि बज चुकी थी। बिहार का यह राजनीतिक स्वभाव ही भाजपा के लिए सीमा बन जाती है, जिससे पार पाने की जुगत में मोदी अभी से जुट गए हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के त्रिकोण पर हमलावर होते हुए वे एक ऐसा चुनावी नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे, जिस पर नई पीढ़ी आकर्षित हो जाती है और उसके विरुद्ध बोलते हुए विरोधी दलों की जुबान भी लड़खड़ाने लगती है।

परिवारवाद, भ्रष्टाचार व अपराध पर हुआ कोई भी राजनीतिक प्रहार सीधे लालू-राबड़ी परिवार को आहत करता है। वह परिवार जो तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद पिछले चार दशक से बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। भाजपा को उसके विरोध का बहुत लाभ है, लेकिन जदयू से अलगाव पर लाभ की आशा क्षीण हो जाती है। यही कारण है कि भाजपा उसी क्षण से अंदरखाने नीतीश कुमार को फिर रिझाने-मनाने में जुट गई थी, जब वे महागठबंधन के हमराही हुए थे। नीतीश को अपने साथ जोड़ लेना भाजपा की पहली रणनीतिक विजय है। उसे पता है कि जातियों में बंटे बिहार की राजनीति में जदयू के साथ गठबंधन का होना उसके लिए कितना आवश्यक है और अलगाव में क्या नुकसान हो सकता है। कुछ माह पहले के चुनावी सर्वेक्षण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को बिहार में पुराने प्रदर्शन से कुछ कमतर स्थिति में बताया गया था। हिंदीभाषी राज्यों में उसकी सबसे खराब स्थिति यहीं पर पाई गई। तब नीतीश महागठबंधन के साथ थे। लाभ-हानि के इस गणित को 2015 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्रमशः महागठबंधन और राजग की सफलता से समझा जा सकता है। वर्ष 2015 में नीतीश महागठबंधन के साथ, जबकि 2019 में राजग के साथ। तब बिहार में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजग 40 में से 39 संसदीय क्षेत्रों में विजयी रहा। उसकी झोली में 53 प्रतिशत मत आए। महागठबंधन का वह सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन रहा। उसे एकमात्र किशनगंज संसदीय क्षेत्र में सफलता मिली थी। इस बार राजग किशनगंज को भी हथियाने के प्रयास में है और इस संघर्ष में उसे एआइएमआइएम से बड़ी सहायता मिल सकती है, जो वर्ग विशेष के वोटों को बांट कर संभावित परिणाम में उलटफेर करता रहा है। गोपालगंज विधानसभा का उप-चुनाव इसका प्रमाण है। ध्रुवीकरण की तरह ही वोटों के बंदरबांट पर भी राजग बीच के रास्ते से सहजता से निकल जाएगा। यही कारण है कि मोदी उपरोक्त त्रिकोण की चर्चा के साथ श्रीरामजन्मभूमि व सनातन संस्कृति के दूसरे प्रतीकों का भी उल्लेख कर जनमानस को झकझोर रहे।

छह मार्च को बेतिया में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फाइल

प्रतिबद्ध मतदाता तो पार्टियों के लिए बंधुआ की तरह हैं। दोराहे पर खड़े तटस्थ मतदाता ही जीत-हार के निर्णायक होते हैं और चुनावी इतिहास बताता है कि भावनात्मक मुद्दों पर वे कैसे रिझाए जाते रहे हैं। मोदी अपना यह दांव भी चल चुके हैं, जबकि प्रत्युत्तर में राहुल जाति और न्याय के मुद्दे का उल्लेख कर रहे और वह भी बिखरे हुए अंदाज में। राहुल इस सच की अनदेखी कर रहे कि पिछड़ी जातियों के मुद्दे पर उन्होंने काफी देरी कर दी है और वे कांग्रेस की मास वाली छवि से जातिगत राजनीति की ओर बढ़ रहे, जो दोधारी तलवार जैसी है। मोदी जब कहते हैं कि मैं सूर्य-चंद्रयान की बात कर रहा और विरोधी लालटेन युग की ओर धकेल रहे तो बिहार की वह जनता भी झूम उठती है, जो देश में प्रति व्यक्ति सबसे कम आय वाले राज्य की निवासी है।

मोदी के बरअक्श आकर राहुल आज जिस संकट का सामना कर रहे, वह अतीत की तुलना में अधिक गंभीर है। कांग्रेस लोकसभा में 53 सीटों पर सिमट चुकी है, जबकि देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले हिंदीभाषी व पश्चिमी राज्यों में मोदी का बोलबाला है। आज संसद तक पहुंचने के लिए राहुल सड़क पर संघर्ष कर रहे, जबकि अंदरखाने कांग्रेस की स्थिति भी सामान्य नहीं। दिल्ली से लेकर बिहार तक खलबली है। यह खलबली जितनी अधिक बढ़ेगी, तटस्थ मतदाताओं को मोदी उतना ही अधिक अपनी ओर खींचते जाएंगे। इसका कारण यह कि भाजपा ने अपनी विचारधारा की निरंतरता बनाए रखी है, जबकि कांग्रेस में उसका बिखराव हुआ है। इसीलिए मोदी का संवाद सहजता से लक्षित समूह तक पहुंच जाता है। राहुल की बातें जनता तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाती हैं और कांग्रेस-जन उसके लिए फिर से प्रयास भी नहीं करते।

मंथन

डा. मनसुख मांडविया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक मंत्री

विकसित भारत का संकल्प

वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' का संकल्प देश के सामने रखते हुए 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, '2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले पांच साल हैं और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके समार्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है उसका गौरवगान उससे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।'

मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री अपने लगभग एक दशक के कार्यकाल में जो भी कहा है, उसे उन्होंने पूरा किया है। यही कारण है कि देश के लोग प्रधानमंत्री की कही हुई बातों को 'मोदी की गारंटी' मानते हैं। मोदी जी ने जब लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत बनाने का संकल्प रखा तो इसमें उन्होंने जनसहभागिता की भी बात की। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं को सैचुरेशन मोड में आगे ले जाना होगा।

इसके लिए मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड से 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' की शुरुआत की। 'हमारा संकल्प, विकसित भारत' के मूल मंत्र के साथ इस यात्रा के दौरान मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव तक गई और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उन योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही कई बीमारियों के लिए बड़ी संख्या में लोगों की स्क्रीनिंग की, बहुत बड़ी संख्या में 'माइ भारत वालंटियर' बनाए और ड्रोन का प्रदर्शन करके देश की कृषि को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में रचनात्मक प्रयास किया। हालांकि जब इस यात्रा का शुभारंभ मोदी जी ने किया था तो उस समय हमेशा नकारात्मक राजनीति करने वाले विपक्षी नेताओं ने इस यात्रा की सफलता पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व और इस देश के जन-जन का विकसित भारत के निर्माण के प्रति संकल्प ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को एक सफल यात्रा बना दिया। 15 नवंबर 2023 से तीन मार्च 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंची। इस बीच इस यात्रा के तहत कुल 2.82 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश की लगभग 2.62 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया गया।

इस यात्रा के दौरान लगभग एक करोड़ लाभार्थियों ने 'मेरी कहानी, मेरी जुबानी' के माध्यम से यह बताया कि मोदी सरकार की योजनाएं कैसे उनके जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 2.52 लाख 'धरती कहे पुकार के' कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। विकसित भारत के मोदी जी के संकल्प को सभी देशवासियों की सहभागिता का भाव यहीं नहीं थमा, बल्कि इस यात्रा के दौरान जो विभिन्न कैंप आयोजित हुए, उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में लागू हुए।

मोदी जी ने 'स्वस्थ भारत' का संकल्प देश के सामने रखा है। इस संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इन स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 7.34 करोड़ लोग आए। वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से इन शिविरों में आए लगभग 3.9 करोड़ लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 11.9 लाख लोगों को टीबी के इलाज के लिए रेफर किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कई तरह की मदद हासिल करने के लिए 4.23 लाख लोगों ने अपनी सहमति दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में रिकार्ड 1.21 लाख लोग निक्षय मित्र बने और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इन शिविरों में टीबी मरीजों के 90 हजार बैंक खाते से संबंधित जानकारियां ली गईं, ताकि इन मरीजों के बैंक खाते में सीधे निक्षय पोषण योजना का लाभ पहुंच सके। ये आंकड़े बताते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने फिर से यह संकल्प दोहराया कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की गारंटी देने वाली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इस उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान तकरीबन 2.79 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए।

मोदी सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की दिख रही भागीदारी। फाइल

विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक करोड़ से अधिक पुरस्कार महिलाओं, छात्रों, स्थानीय खिलाड़ियों और स्थानीय कलाकारों के बीच बांटे गए। सही मायने में देखा जाए तो विकसित भारत संकल्प यात्रा इस देश के जन-जन को प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के संकल्प से जोड़ने और इस लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा में सहभागी बनाने की यात्रा साबित हुई है। इस यात्रा में देश के हर क्षेत्र के समाज के हर वर्ग के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कहीं से भी विरोध की कोई बात नहीं आई। यह दिखाता है कि आम जनता का मोदी जी के प्रति विश्वास कितना दृढ़ है।

****